देशबन्धु

वर्ष – 9 । अंक –242 । भोपाल, गुरुवार 3 सितम्बर 2026 । पृष्ठ–8 । मूल्य – 2.00 रुपए

आधुनिक तकनीक और नई पीढ़ी के कौशल से सुसज्जित होगा नया केन्द्र — पृष्ठ 2
▸ छवियों में कैद मोदी विदेश नीति ▸ बच्चों की डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित — पृष्ठ 4
▸ बैरकों की नशीले पदार्थों की हुई चैकिंग, हथियार, मोबाइल और प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली — पृष्ठ 6
जिसके हाथ में हल, वही देश का असली बल : डॉ. यादव — पृष्ठ 8

सार-समाचार

एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने थामा कांग्रेस का दामन

नई दिल्ली, देशबन्धु। टीवी चैनलों पर काफी मुखर नजर आने वाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता आसिम वकार बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यूपी के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। इस मौके पर वकार ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सेक्युलरिज्म और सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें कांग्रेस का दामन थामने का फैसला लिया है। एआईएमआईएम तो भाजपा से लड़ने के बजाए उस विपक्ष से लड़ रही है, जो भाजपा को सत्ता से हटाना चाहता है।

दिल्ली में 65 लाख रुपए मूल्य की अवैध सिगरेट जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली सरकार ने नियमित जांच के दौरान 65 लाख रुपये मूल्य की अवैध सिगरेट ले जा रहे एक वाहन को यहां जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह खेप व्यापार और कर विभाग की कर चोरी विरोधी शाखा की टीम की रात्रि छापेमारी में पकड़ी गयी है। वाहन में दक्षिण कोरिया की आयातित सिगरेट के चार लाख से अधिक पैकेट ले जाये जा रहे थे, जिसे अक्सर तस्करी के जरिये भारतीय बाजार में लाया जाता है। यह भारत में बेचे या वितरित किये जाने वाले तंबाकू उत्पादों पर लागू कानूनी मानकों का उल्लंघन था।

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर 1.93 किलोग्राम गांजा जब्त

अहमदाबाद, एजेंसी। अहमदाबाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने बुधवार को ट्रॉली बैग के अंदर विशेष रूप से बनाए गए स्थान से 1.928 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त करने में सफलता पाई। इसके साथ ही बैंकॉक से आए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया। यह सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (एसवीपीआईए) पर दो दिनों में दूसरी ऐसी जब्ती है। यात्रियों की प्रोफाइलिंग और एक्स-रे स्कैनिंग के आधार पर कार्रवाई करते हुए अहमदाबाद सीमा शुल्क की वायु खुफिया इकाई (एआईयू) के अधिकारियों ने बैंकॉक से थाई एयरवेज की उड़ान टीजी-343 से आए दो यात्रियों को रोका।

भारतीय विरासत की झलक, बार्सिलोना पहुंचा आईएनएस सुदर्शिनी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय नौसेना का 'आईएनएस सुदर्शिनी' बार्सिलोना पहुंच गया। 'आईएनएस सुदर्शिनी' एक बेहद खास पाल वाला पारंपरिक शैली का पोत है। यह लंबी समुद्री यात्रा पर है। बार्सिलोना पहुंचने के साथ ही इस ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। दरअसल यह यात्रा भारतीय नौसेना के अंतरमहाद्वीपीय समुद्री अभियान 'लोकायन 2026' का हिस्सा है। लोकायन के माध्यम से भारत विश्व में शांति और मित्रता का संदेश दे रहा है। आईएनएस सुदर्शिनी के स्पेन पहुंचने से यहां दोनों देशों के बीच समुद्री साझेदारी आपसी सहयोग व संपर्क बढ़ेगा।

कुकी-जो विधायक मणिपुर विधानसभा सत्र में हुए शामिल

इंफाल, एजेंसी। कुकी-जो समुदाय के दो विधायक तीन साल से अधिक समय में पहली बार बुधवार को मणिपुर विधानसभा सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। मणिपुर विधानसभा के 12वें सत्र का आठवां सत्र बुधवार को इंफाल में शुरू हुआ, जिसमें कुकी-जो समुदाय से संबंधित पहाड़ी क्षेत्रों के विधायक 3 मई, 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पहली बार कार्यवाही में शामिल हुए। सैतु विधानसभा क्षेत्र से विधायक हाओखोलेट किपगेन और साइकुल विधानसभा क्षेत्र से विधायक किमनेओ हाओकिप हैंगशिंग बुधवार को सत्र की पहली बैठक के दौरान उपस्थित थे। तीन साल से अधिक के अंतराल के बाद सदन में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई है, इस दौरान कुकी-जो समुदाय के प्रतिनिधियों ने इम्फाल में विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था। मणिपुर विधानसभा में प्रवेश करते हुए हाओखोलेट किपगेन ने कहा कि वह लंबे समय बाद विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए वापस आकर खुश हैं। हालांकि, उपमुख्यमंत्री नेमचा किपगेन ने वर्चुअल मोड में सत्र में भाग लिया। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए इसे राज्य में एकता और शांति को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया।

---

106 करोड़ की भदोरा इंडस्ट्रीज का लोकार्पण, बोले मुख्यमंत्री

उद्योगों को रफ्तार, युवाओं को रोजगार

सिंगल विंडो से त्वरित अनुमति और आसान भूमि आवंटन से निवेशकों को मिल रहा अनुकूल वातावरण

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। राज्य सरकार उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को लगातार सरल बना रही है और सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को त्वरित अनुमतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को ग्वालियर से वर्चुअली खरगोन जिले की कसरावद तहसील के ग्राम पानवा में 106.35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित भदोरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के शुरू होने से कसरावद क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले उद्योग लगाने के लिए 76 प्रकार की अनुमतियां लेनी पड़ती थीं, लेकिन अब सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया गया है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया, जो पहले 50 से 60 दिन में पूरी होती थी, अब 29 दिन के भीतर पूर्ण करने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना, नवकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खरगोन कपास उत्पादन के लिए विशेष पहचान रखता है और उद्योगों के विकास से किसानों तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ धार्मिक पर्यटन और अधोसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश-विदेश की अनेक औद्योगिक इकाइयां प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उन्होंने उद्यमियों से मध्य प्रदेश में निवेश कर रोजगार और समृद्धि के नए अवसर सृजित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भदोरा इंडस्ट्रीज के संचालन से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी और कसरावद क्षेत्र आर्थिक प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।

जनविश्वास अभियान को नई मजबूती देगा जनविश्वास पोर्टल : डॉ. यादव

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में जनविश्वास पोर्टल महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर यूजर मैनुअल के अनुसार अभियान से संबंधित जानकारियां नियमित रूप से अपलोड की जाएं, ताकि मैदानी स्तर पर जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

अधिकारियों को नियमित जानकारी अपलोड करने के निर्देश, उच्च स्तर पर होगी साप्ताहिक समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि 7 अगस्त से शुरू हुआ अभियान चार सप्ताह सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और कम समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी सप्ताह में एक दिन मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण करने के लिए यह पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भ्रमण, निरीक्षण, जनसंवाद, उद्यम संवाद, जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों, नीतिगत विषयों, महत्वपूर्ण निर्देशों, जिलों के नवाचारों तथा सुझावों की जानकारी दर्ज की जाएगी।

राममंदिर के पहले सीईओ बने जीतेंद्र मिश्रा

- भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल हैं
- गोविंददेव गिरि को महासचिव का दायित्व

अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की प्रशासनिक और संचालन व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा कदम उठाया है। ट्रस्ट ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को मंदिर का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया। इसके तहत स्वामी गोविंददेव गिरि को महासचिव बनाया गया है, जबकि महेश भागचंदका को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। मंदिर में आने वाले नकद चढ़ावे की गणना प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और तकनीक आधारित बनाने पर भी बैठक में विशेष जोर दिया गया।

जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना में करीब चार दशक तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने छह दिसंबर 1986 को फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया था। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के 18 से अधिक विमानों पर उड़ान भरी और तीन हजार घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव हासिल किया। जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ भी रह चुके हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में लंबे समय से रिक्त चल रहे तीन सदस्य पदों को बुधवार को भर दिया गया। मणिराम दास जी की छावनी में आयोजित ट्रस्ट की बैठक में नए सदस्यों के नामों पर मुहर लगाई गई। ट्रस्ट में चंपतराय, अनिल मिश्रा और स्वर्गीय विमलेन्द्र मोहन मिश्रा के स्थान पर अयोध्या के मदन मोहन पाण्डेय, दिल्ली के महेश भागचंदका और शिकोहाबाद की डा निर्मला यादव को सदस्य नियुक्त किया गया है। निर्मला यादव विश्व हिंदू परिषद के निधि समर्पण अभियान से जुड़ी रही हैं। दिल्ली निवासी महेश भागचंदका विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल के रिश्तेदार हैं। वह अशोक सिंघल फाउंडेशन से जुड़े हैं। अयोध्या निवासी मदन मोहन पाण्डेय वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और राम मंदिर से जुड़े मुकदमों की पैरवी कर चुके हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार का अपर महाधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था।

राहुल गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत, नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

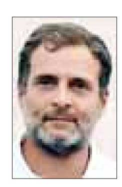

लखनऊ, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनकी भारतीय नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने के बाद खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। अशोक पांडेय और एक अन्य की ओर से दाखिल याचिका में राहुल गांधी के रायबरेली से लोकसभा सदस्य बने रहने के अधिकार को चुनौती देते हुए क्वो वारंटो रिट जारी करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी भारतीय नहीं, बल्कि ब्रिटिश नागरिक हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि इसी मुद्दे पर वर्ष 2015 और 2019 में भी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।

आंध्र प्रदेश में गोल्लागुप्पा गांव में हुई घटना

मलेरिया की दवा लेने के बाद 70 बीमार, बच्ची की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। आंध्र प्रदेश के गोल्लागुप्पा गांव में मलेरिया रोकथाम अभियान के दौरान स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र द्वारा मलेरिया की गोलियां दिए जाने के बाद कथित तौर पर एक सात वर्षीय आदिवासी लड़की की मौत हो गई और छात्रों और ग्रामीणों सहित 70 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने व्यापक जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को प्रभावित लोगों के उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

गोलगुप्पा पोलावरम एजेंसी। क्षेत्र का एक आदिवासी गांव है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों द्वारा मलेरिया की जांच के बाद 1 सितंबर को आदिवासी छात्रों और ग्रामीणों सहित गांव की आबादी में दवा वितरित की गई। दवा लेने के बाद बीमार पड़ने वालों में 14 आंगनबाड़ी बच्चे, 40 आदिवासी छात्र और 18 ग्रामीण शामिल हैं। गोलियां लेने के बाद गंभीर रूप से बीमार हुए लोगों को बेहतर इलाज के लिए तेलंगाना के भद्राचलम एरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। पोलावरम जिले के कलेक्टर के. दिनेश कुमार ने बुधवार को फोन पर राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सत्य कुमार को गुल्लागप्पा की नवीनतम स्थिति के बारे में जानकारी दी और कहा कि इलाज करा रहे ग्रामीणों की हालत स्थिर है। मलेरिया की गोलियां खाने वालों में जीपीएस स्कूल की कक्षा 2 की छात्रा सात वर्षीय मादिवी जमुना भी शामिल थी। दवा खाने के बाद उसे तेज उल्टी और पेट में जलन होने लगी। उसे तुरंत पास के लक्ष्मीपुरम पीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एम्बुलेंस से तेलंगाना के भद्राचलम स्थित क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि, अस्पताल पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। उस दिन शाम तक, गांव के कई और बच्चों में पेट दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखने लगे।

चंद्रपुर: सरकारी स्कूल के खाने में छिपकली मिलने से 30 छात्र बीमार

चंद्रपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक सरकारी आश्रम स्कूल के खाने में छिपकली मिलने से कम से कम 30 छात्र बीमार हो गए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यह घटना मंगलवार को जीवती तालुका के नागराला गांव में अंब्रू नाइक माध्यमिक आश्रम स्कूल में उस समय हुई, जब स्कूल में छात्रों को खाना परोसा गया। खाना खाने के तुरंत बाद कई छात्रों को जी मिचलाने, उल्टी और पेट में तकलीफ की शिकायत हुई। बीमार छात्रों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि खाना बनाते समय उसमें छिपकली गिर गई होगी, जिससे छात्रों को फूड पॉइजनिंग होने का शक है। सभी छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने खाने के नमूने प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए हैं और घटना की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद छात्रों के माता-पिता ने इस लापरवाही पर रोष जाहिर किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही संस्थान में साफ-सफाई और खाने पान सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ईडी ने कई राज्यों में 14 जगहों पर की तलाशी

टोल चोरी सिंडिकेट से जुड़े संदिग्धों पर मारे छापे

अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी टोल रसीदें बनाकर फंड डाइवर्ट करने का खेल

नई दिल्ली, देशबन्धु। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी से टोल वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। ईडी ने बुधवार को एक साथ कई राज्यों में 14 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता स्थित परिसरों पर तलाशी ली जा रही है।

जानकारी के मुताबिक ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बुधवार तड़के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान , महाराष्ट्र, जम्मू, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने कुछ सूचनाओं के आधार पर इस मामले से जुड़े संदिग्धों के परिसरों पर तलाशी अभियान शुरू किया है। आरोप है कि अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी टोल रसीदें बनाई जा रही थी। इसके अलावा टोल से मिलने वाली रकम को एनएचएआई के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट किया जा रहा था। फॉरेंसिक जांच और एनएचएआई के रिकॉर्ड में ऐसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि भी हुई है। ईडी की टीम डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जुटा रही है। वहीं ईडी रकम के असली लाभार्थियों और मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है। टोल संचालकों, आईटी कर्मियों और आरोपियों के बीच रकम बांटने का आरोप है। ईडी छापेमारी के दौरान डिजिटल रिकॉर्ड खंगाल रही है।

केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई टोल संचालक

यूपी एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर कई टोल संचालक हैं। वाराणसी से टोल घोटाले के कथित मास्टरमाइंड आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उस पर हरहुआ में रहकर अवैध नेटवर्क ऑपरेट करने का आरोप है। वाराणसी के लाला नगर टोल प्लाजा पर 62.87 करोड़ की स्टांप चोरी के मामले की भी जांच चल रही है। जाँच एजेंसी देशभर के 200 से अधिक टोल प्लाजा की जांच कर रही है, जिनमें से 100 के करीब यूपी के टोल प्लाजा हैं।

सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र सरकार को झटका

ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण फैसले पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, देशबन्धु। ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण पर केंद्र सरकार को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुराने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने मामले में केंद्र सरकार को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों को 17 सितंबर 2026 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण मामले में केंद्र सरकार की स्पष्टीकरण याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने केंद्र सरकार को कोई भी अंतरिम राहत देने या अपने पिछले आदेश के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पष्टीकरण याचिका दायर कर इस फैसले को लागू करने में आ रही व्यावहारिक चुनौतियों का ब्योरा दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से यूपीएससी परीक्षा 2025 की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि यूपीएससी के अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सर्विस एलोकेशन की प्रक्रिया पुराने नियमों के मुताबिक फाइनल स्टेज में थी।

करगिल-लेह पदयात्रा के लिए लद्दाख में तैयारियां तेज

लद्दाख में अधिकार पाने की जंग शुरू, शांतिपूर्ण आंदोलन का ऐलान

केडीए ने पूर्ण समर्थन का वादा किया

जम्मू, देशबन्धु। लद्दाख में अधिकार पाने की जग की शुरूआत हो गई है। पहले चरण में पदयात्रा की घोषणा की गई है और करगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (केडीए) ने 10 से 24 सितंबर तक करगिल और लेह के बीच होने वाली पदयात्रा को अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। इस पदयात्रा का उद्देश्य लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में इस क्षेत्र को शामिल करने की मांगों को बल देना है, साथ ही 24 सितंबर की घटनाओं के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करना है। गठबंधन ने लद्दाख के लोगों के संवैधानिक और वैध अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संघर्ष के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। पदयात्रा को समर्थन देने का निर्णय केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई और स'जाद करगिली के साथ-साथ अन्य केडीए सदस्यों और संबंधित हितधारकों की उपस्थिति में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया।

केडीए के सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गठबंधन लद्दाख के लोगों के संवैधानिक, लोकतांत्रिक और वैध अधिकारों को शांतिपूर्ण तरीकों से लगातार हासिल करने का प्रयास करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और भारत सरकार करगिल और लेह जिलों के निवासियों के वैध अधिकारों और मांगों को स्वीकार नहीं कर लेते और उन पर ध्यान नहीं देते। लद्दाख की आकांक्षाओं के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी और विभिन्न नागरिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्षेत्र की सामूहिक आवाज को उजागर करना है।

10 को करगिल से शुरू होगी

प्रस्तावित पदयात्रा 10 सितंबर को करगिल से शुरू होगी, और हनीस्कोट तक समन्वय की जिम्मेदारी केडीए की होगी। हनीस्कोट से आगे लेह तक का समन्वय लेह एपेक्स बाडी (एलएबी) द्वारा किया जाएगा। यह रैली 24 सितंबर को लेह में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ समाप्त होगी। यह पदयात्रा 24 सितंबर, 2025, जो एक त्रासदी का दिन था जब लेह में विरोध प्रदर्शनों के दौरान चार युवाओं ने अपनी जान गंवाई थी, की घटनाओं की याद में आयोजित की जा रही है जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए और हिरासत में लिए गए। इस पदयात्रा का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करना और न्याय, जवाबदेही और इस घटना के कारणों के निर्णायक समाधान के लिए दबाव बनाना है। सांसदों, नागरिक समाज प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और देश भर की जानी-मानी हस्तियों सहित कई प्रमुख व्यक्तियों के इस पदयात्रा में शामिल होने की उम्मीद है।

सार-समाचार

10 लाख के नशीले पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार

शिवपुरी, देशबन्धु। कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को स्मैक का विक्रय करते हुए धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 38.50 ग्राम स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई गई है, बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल कीमत करीब 50 हजार रुपए और एक मोबाइल फोन कीमत करीब 5 हजार रुपए भी जब्त किया। कार्रवाई में कुल 10 लाख 55 हजार रुपए की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

करेरा थाने में विधायक निधि से लगा वाटर फ्रीजर सुधारने की उठी मांग

दिनारा, देशबन्धु। जल ही जीवन है और प्यासे व्यक्ति को शुद्ध एवं ठंडा पानी उपलब्ध कराना सबसे बड़ी मानव सेवा माना जाता है। इसी सोच के साथ करेरा क्षेत्र के विधायक रमेश खटीक द्वारा विधायक निधि से करेरा थाना परिसर में आमजन की सुविधा के लिए ठंडे पेयजल का फ्रीजर लगवाया गया था। हालांकि, स्थानीय समाजसेवियों ने बताया है कि उक्त वाटर फ्रीजर पिछले कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसके कारण थाना परिसर में आने वाले आम नागरिकों को ठंडे एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। करेरा थाना क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा का सुचारु रहना अत्यंत आवश्यक है। समाजसेवी अर्जुन पंडित ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जनहित के उद्देश्य से लगाया गया फ्रीजर आज अपनी खराब स्थिति के कारण स्वयं उपेक्षा की कहानी बयां करता नजर आ रहा है। वहीं समाजसेवी जितेंद्र लोधी ने बताया कि करेरा थाने में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आमजन आते हैं। कई लोग दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पहुंचते हैं। ऐसे लोगों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होना बेहद जरूरी है।

शहर में विशेष स्वच्छता अभियान तेज

शिवपुरी,देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अर्पित वर्मा के निर्देशन तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत राठौर के मार्गदर्शन में नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को सुबह एवं दोपहर के समय शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों, वार्डों, बाजारों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान झाड़ू लगवाने, नालियों की सफाई, डंप कचरा उठाने, सड़क किनारे जमा कचरे को हटाने तथा आवश्यक स्थानों पर सफाई एवं धुलाई की कार्रवाई की गई। सुबह के समय कोर्ट रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। यहां नालियों की सफाई कराने के साथ सड़क पर झाड़ू लगवाकर कचरा हटाया गया। इसी क्रम में सर्किट हाउस रोड की नालियों की सफाई कराई गई तथा सड़क किनारे जमा कचरे को भी उठाया गया। दो बत्ती चौराहा क्षेत्र में विशेष सफाई एवं धुलाई कराकर क्षेत्र को स्वच्छ एवं व्यवस्थित किया गया। थीम रोड मार्केट में भी सफाई अभियान चलाकर सड़क एवं आसपास के क्षेत्रों से कचरा हटाया गया। नगर पालिका द्वारा सर्कुलर रोड के विभिन्न हिस्सों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। पोहरी चौराहे से नक्षत्र गार्डन की ओर जाने वाले मार्ग पर सफाई कराई गई। इसके साथ ही ग्वालियर बायपास से नक्षत्र गार्डन तक सर्कुलर रोड की सफाई कराई गई। पीएस होटल से नक्षत्र गार्डन तक तथा ग्वालियर बायपास से सेंड वेंटेड स्कूल तक सर्कुलर रोड पर भी झाड़ू लगवाकर सफाई कराई गई। घोड़ा चौराहा से गुना बायपास तक दोपहर के समय सड़क की सफाई कराने के साथ डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहन से कचरा उठवाया गया।

केन्द्रीय मंत्री ने शिवपुरी में रखी देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला, कहा

आधुनिक तकनीक और नई पीढ़ी के कौशल से सुसज्जित होगा नया केन्द्र

- डाक कर्मचारियों को अब प्रशिक्षण के लिए लगभग 6 सौ किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा
- -2 वर्षों में डाक विभाग के राजस्व में 2,155 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि

शिवपुरी, देशबन्धु। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को शिवपुरी में देश के 7वें पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का भूमिपूजन किया। यह केन्द्र डाक विभाग के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के तंत्र को मजबूत करने के साथ मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के डाक कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक और नई पीढ़ी के कौशल का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप यह केन्द्र डाक विभाग को बदलते समय की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना से मध्य प्रदेश के डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए लगभग 600 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिवपुरी में ही उन्हें आधुनिक सुविधाओं और नई तकनीकों से युक्त प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि शिवपुरी का यह पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर देश में पहले से संचालित छह पोस्टल ट्रेनिंग सेंटरों की श्रृंखला का विस्तार है। वर्तमान में सहारनपुर, वडोदरा, मैसूर, गुवाहाटी, मदुरई और दरभंगा में ये केन्द्र संचालित हैं और प्रतिवर्ष लगभग 2,000 डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी अपनी भौगोलिक स्थिति एवं कनेक्टिविटी के कारण राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थान है। यहां डाक कर्मचारियों को विशेषज्ञता आधारित, तकनीक-सक्षम और नई पीढ़ी के प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि डाक सेवा को डिजिटल बनाकर 140 करोड़ भारतीयों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जिस डाक विभाग में कभी वार्षिक राजस्व वृद्धि 100-200 करोड़ रुपये के आसपास हुआ करती थी, उसी विभाग का राजस्व वर्ष 2024 में 13,218 करोड़ था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 15,296 करोड़ हो गया। यानी केवल एक वर्ष में 2,078 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई है। इस अवसर पर शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र यादव, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया, जिला अध्यक्ष जसमंत जाटव, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष हेमलता रावत, कर्नल एस.एफ.एच.रिजवी , चीफ पोस्ट मास्टर जनरल विनीत माथुर, पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक, प्रहलाद भारती, भैया साहब लोधी, राजू बाथम एवं हरवीर रघुवंशी आदि उपस्थित रहे।

शिवपुरी सहित गुना और ग्वालियर के 3 डाकघरों का लोकार्पण: केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी प्रवास के दौरान शिवपुरी के अत्याधुनिक मुख्य डाकघर का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने गुना और ग्वालियर के तीन अन्य डाकघरों का भी लोकार्पण किया। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये डाकघर नागरिकों को बेहतर, सुगम और अधिक प्रभावी डाक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। शिवपुरी का यह नया डाकघर जनसेवा कनेक्ट डाकघर पहल के मानकों पर आधारित है, जिसमें नागरिक-केंद्रित सुविधाओं, बेहतर अनुभव और सुगम सेवा वितरण का विशेष ध्यान रखा गया है।

छात्रावास अधीक्षक निलंबित, व्यवस्थाओं में लापरवाही पर कलेक्टर की सख्ती

इंदरगढ़ के अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास का मामला

भोपाल, देशबन्धु । दतिया जिले के इंदरगढ़ स्थित अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक डॉ. डी.आर. राहुल को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं।तहसीलदार इंदरगढ़ द्वारा छात्रावास के निरीक्षण के बाद प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह कार्रवाई की। डॉ. राहुल को मध्य प्रदेश सिविल सेवा अपील, नियंत्रण एवं वर्गीकरण नियम-1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनजातीय कार्य विभाग, दतिया निर्धारित किया गया है। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि छात्रावास में विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू और मानकों के अनुरूप ताजा, गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही छात्रावास परिसर, आवासीय कक्षों, रसोईघर, शौचालय और स्नानागारों की नियमित साफ-सफाई तथा स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और बीमार छात्रों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने को भी कहा गया है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को छात्रावास का नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों की उपेक्षा अथवा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रेवंत रेड्डी ने राजनाथ सिंह से की मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें सात से नौ दिसम्बर तक भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट-2026 में शामिल होने का न्योता दिया। रेड्डी ने रक्षा एक्सपो-2026 का उद्घाटन करने का भी आग्रह किया।

राजताला में धूमधाम से मनाई लव-कुश जयंती

कुशवाहा बने ब्लॉक अध्यक्ष

अशोकनगर, देशबन्धु। ग्राम राजताला में भगवान श्री लव-कुश जयंती के अवसर पर एक भव्य सामाजिक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व कुश बोर्ड अध्यक्ष व अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा तथा जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाजजन गरिमामयी उपस्थिति में शामिल हुए। इस पावन अवसर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने और समाज को नई दिशा देने के उद्देश्य से जिलाध्यक्ष उत्तम कुशवाहा द्वारा विक्रम कुशवाहा को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का अशोकनगर ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति पर उपस्थित समाजबंधुओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में सामाजिक हितों के लिए बेहतर कार्य होंगे।

सभा के दौरान वक्ताओं ने भगवान श्री लव-कुश के आदर्शों को जीवन में उतारने, आपसी एकता और भाईचारा मजबूत करने तथा युवाओं को संगठन से जोड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष सविता कुशवाहा, युवा अध्यक्ष गौरव कुशवाहा (देरखा), चंदन कुशवाहा, हंसराज कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, सीताराम कुशवाहा और नीरज पटेल सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने किया ग्वालियर में प्रतिमा का अनावरण

भोपाल, देशबन्धु । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जननेता और समाजसेवी स्व. रघुवीर सिंह बाबूजी ने अपना पूरा जीवन जनसेवा और नागरिक अधिकारों के संघर्ष को समर्पित किया। उनके कार्यों और आदर्शों का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियां करेंगी और ग्वालियर में स्थापित उनकी प्रतिमा लोगों को जनसेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। मुख्यमंत्री बुधवार को ग्वालियर के आकाशवाणी तिराहे पर पूर्व विधायक एवं नगर निगम परिषद के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्व. रघुवीर सिंह बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे। उन्होंने आकाशवाणी तिराहे का नाम बदलकर स्व. रघुवीर सिंह बाबूजी के नाम पर करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. बाबूजी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा ली और युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्व. माधवराव सिंधिया के साथ नगर निगम से विधानसभा तक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और सदैव जनता की आवाज बुलंद की।

गोरा टीला झरने में 4 मासूमों की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट

50 लोगों के खून के नमूने लिए, पानी की जांच शुरू

एसडीएम ने किया मौके का निरीक्षण

शिवपुरी, देशबन्धु। जिले के ग्राम गोरा टीला स्थित झरने के पानी के उपयोग के बाद चार मासूम बच्चों की मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस घटना में चार बच्चों की असमय मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अरविंद वर्मा के निर्देश पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल जांच एवं निगरानी अभियान शुरू कर दिया है। घटना के बाद पिकनिक में शामिल रहे परिजनों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए करीब 50 ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। वहीं, गोरा टीला स्थित झरने के पानी के भी सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गए हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर चार मासूम बच्चों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या रहा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलारस एसडीएम शिवदयाल धाकड़ ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को क्षेत्र में व्यापक सर्वे करने और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से विशेष सतर्कता बरतते हुए ग्रामीणों और आसपास के लोगों से अपील की गई है कि जांच रिपोर्ट आने तक गोरा टीला झरने के पानी का किसी भी प्रकार से उपयोग न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि झरने के पानी को फिलहाल पीने, नहाने अथवा घरेलू उपयोग में न लिया जाए।

पीड़ित परिवारों को दी गई आर्थिक सहायता: इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है। रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1 लाख 50 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। चार मासूम बच्चों की मौत ने पूरे शिवपुरी जिले को झकझोर कर रख दिया है। अब सभी की निगाहें ब्लड और पानी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे इस दर्दनाक घटना की असली वजह सामने आ सकेगी।फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें, सावधानी बरतें और जांच पूरी होने तक गोरा टीला झरने के पानी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें।

नरवर-सतनवाड़ा मार्ग पर रात में हुई घटना

युवक पर बाघ ने किया हमला, हालत गंभीर

नरवर/शिवपुरी, देशबन्धु। नरवर-सतनवाड़ा मार्ग पर टपकेश्वर मंदिर के नीचे मंगलवार रात करीब 8 बजे एक युवक पर कथित तौर पर शेर ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, ग्राम चकरमपुर निवासी विकास कुशवाहा पुत्र करण सिंह कुशवाह नरवर से मणिखेड़ा डैम की ओर जा रहा था। इसी दौरान टपकेश्वर मंदिर के नीचे अचानक कथित तौर पर शेर ने उस पर हमला कर दिया। हमले में विकास के सिर में गंभीर चोट आई और काफी मात्रा में खून बहने लगा। घटना के बाद रास्ते से गुजर रहे भाजपा नेता बशर अली ने मानवता दिखाते हुए अपनी टीम के साथियों और ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को तत्काल उपचार दिलाने की पहल की। उन्होंने मामले की सूचना शिवपुरी पुलिस अधीक्षक एवं सतनवाड़ा रेंजर माधव सिंह सिकरवार को दी। साथ ही घायल के परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद शिवपुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद नरवर-सतनवाड़ा मार्ग एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवर की मौजूदगी को लेकर लोगों में भय का माहौल है। वन विभाग द्वारा घटना की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि युवक पर हमला किस जंगली जानवर ने किया।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा

दिशा सालियान मौत की सीबीआई करेगी जांच

नई दिल्ली, एजेंसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट ने यह फैसला दिशा के पिता की याचिका पर सुनाया। इसमें उन्होंने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे।

दिशा की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी। घटना के छह दिन बाद, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिले थे। दिशा केस की शुरुआती जांच करीब तीन महीने में बंद कर दी गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आने के बाद 2023 में इसे दोबारा खोला गया और एसआईटी बनाई गई। तब से जांच जारी है। जस्टिस एसवी कोतवाल और आरआर भोसले की बेंच ने 28 अगस्त को दिशा मामले की जांच हत्या के एंगल से कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी को मामले की जांच की जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ एफआईआर में नाम होने से कोई व्यक्ति आरोपी नहीं माना जाएगा। अगर जांच में कुछ नहीं मिलता है तो सीबीआई को समरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हाईकोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समेत जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए।

लखनऊ में पूर्व उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने सड़क धंसी

10 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार, घायल

लखनऊ, एजेंसी। यूपी के लखनऊ में आईटी चौराहे से पहले मुख्य मार्ग पर सड़क धंस गई। इसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर यह गड्ढा यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के आवास के सामने हुआ है। वहां 10 फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। इस गड्ढे में बाइक समेत 2 लोग गिरने से घायल हो गए। बाद में मौके पर मौजूद रहे स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। सड़क धंसने की वजह से यातायात भी बाधित हो गया था।

गड्ढे में गिरने वाले एक शख्स की एक पहचान नितिन प्रजापति के रूप में हुई है। नितिन ने बताया कि बीती रात जब मैं और मेरा भाई घर लौट रहे थे, तो हम दोनों एक गड्ढे में गिर गए क्योंकि बारिश के कारण वह दिखाई नहीं दे रहा था। गिरने के कारण मेरा भाई बेहोश हो गया। किसी ने मुझे गड्ढे से बाहर निकाला। बताया जाता है कि जहां गड्ढा हुआ है, वहां ठीक बगल में सांसद दिनेश शर्मा का घर है। यह गड्ढा लखनऊ यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में, कृषि निदेशक के दफ्तर रोड के दूसरी तरफ है। और ऐसी जगह बारिश में 10 फीट का गड्ढा हो गया। फिलहाल, नगर निगम ने गड्ढा पाट दिया है लेकिन मंगलवार की बारिश ने लखनऊ के वीआईपी और बिजी इलाके की पोल खोल कर रख दी है।

पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश

कलेक्टर ने केन्द्र पर खड़े रहकर कराया राशन वितरित

शिवपुरी, देशबन्धु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुगम एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा राशन वितरण व्यवस्था की स्वयं निगरानी करते हुए शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है।

राशन वितरण से संबंधित शिकायत प्राप्त होते ही कलेक्टर वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने तथा आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डहरवारा राशन दुकान में निरीक्षण के दौरान वितरण एवं स्टॉक से संबंधित अनियमितताएं सामने आने पर कार्यवाही की गई। सेल्समैन सुरेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई और जेल भेजा गया है। इसके बाद कलेक्टर वर्मा स्वयं डहरवारा पहुंचे और अपनी मौजूदगी में राशन वितरण प्रारंभ करवाया, जिससे पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध हो सका।

इसी प्रकार बदरवास के बड़ोखरा में भी राशन वितरण से संबंधित शिकायत पर कलेक्टर वर्मा ने तत्काल मौके पर पहुंचकर अपनी निगरानी में पात्र हितग्राहियों को राशन का वितरण कराया। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशन की उपलब्धता एवं वितरण में किसी प्रकार की बाधा न आए और लंबित खाद्यान्न का शीघ्र वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने देहरदा सड़क पीडीएस दुकान का भी निरीक्षण किया।

कलेक्टर वर्मा ने राशन वितरण व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों की राशन दुकानों का नियमित एवं अनिवार्य निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान स्टॉक, वितरण व्यवस्था तथा हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की विशेष रूप से निगरानी की जाए। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ राशन उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक सुगमता से पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित निराकरण करते हुए हितग्राहियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कलेक्टर अर्पित वर्मा ने राशन कार्डधारियों से अपील की कि राशन प्राप्त करते समय निर्धारित मात्रा के अनुसार तौल अवश्य कराएं तथा राशन प्राप्त होने के बाद ही पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाएं। किसी भी समस्या अथवा अनियमितता की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें। प्रशासन द्वारा पारदर्शी, जवाबदेह एवं हितग्राही-केंद्रित राशन वितरण व्यवस्था के लिए निरंतर निगरानी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

बीआरसी-एपीसी के 525 पदों पर नई चयन प्रक्रिया

4 साल का कार्यकाल, फिर भी सालों से जमे हैं अधिकारी-कर्मचारी; अब परीक्षा से होगा चयन

भोपाल, देशबन्धु। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकासखंड स्रोत समन्वयक (बीआरसी) और सहायक परियोजना समन्वयक (एपीसी) के करीब 525 पदों पर अब नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला स्तर पर आवेदन और चयन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 25 सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे और 30 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। नई प्रक्रिया से उन अधिकारियों-कर्मचारियों के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, जो निर्धारित कार्यकाल से अधिक समय से इन पदों पर जमे हुए हैं।

प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों में बीआरसी के पद भरे जाएंगे। वहीं प्रत्येक जिले में औसतन चार एपीसी पद माने गए हैं। इस हिसाब से करीब 220 एपीसी पदों पर भी नए सिरे से चयन की कार्रवाई होगी। मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा में एपीसी चयन की प्रक्रिया अलग से होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 सितंबर तक जिला स्तर पर विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। 9 अक्टूबर को आवेदनों की पात्रता जांच होगी। 21 अक्टूबर को पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दावा-आपत्ति का अवसर दिया जाएगा। 24 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होगी और 30 अक्टूबर को चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। बीआरसी और एपीसी का कार्यकाल चार वर्ष का निर्धारित है। पिछली बार वर्ष 2019 में परीक्षा के माध्यम से इन पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। वर्तमान में कई पदों पर कार्यरत लोगों के चार वर्ष से अधिक समय पूरा होने के बावजूद पद पर बने रहने की स्थिति सामने आई है। नई चयन प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे पदों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करना है।

चयन के लिए संबंधित पद के अनुसार व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता तथा संबंधित विषय का अनुभव आवश्यक होगा। अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष निर्धारित है। बालिका शिक्षा से जुड़े पदों पर महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता या प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समान अंक होने पर वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा। इस बीच शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश ने उच्च पद के प्रभार पर कार्यरत व्याख्याताओं और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी चयन परीक्षा में शामिल करने की मांग की है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल का कहना है कि ऐसे शिक्षक लंबे समय से शैक्षणिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, इसलिए उनके अनुभव को भी पात्रता में मान्यता मिलनी चाहिए।

सीहोर डीपीसी पर सवाल, 6 साल से पद पर बने रहने का दावा

बीआरसी-एपीसी की नई चयन प्रक्रिया के बीच सीहोर जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को लेकर भी विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान डीपीसी आर आर उईके करीब छह वर्षों से पद पर बने हुए हैं। दावा है कि निर्धारित पद के लिए आवश्यक योग्यता के अभाव के साथ विभागीय परीक्षा में दो बार असफल होने के बावजूद वे पद पर बने हुए हैं। सूत्रों के अनुसार करीब दो माह पहले उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र के एक अधिकारी के कथित संरक्षण के बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और वे पुन: पद पर बने हुए हैं। इस मामले को लेकर विभागीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर भी देखते हैं, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यता और चयन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो इतने लंबे समय तक पद पर बने रहना गंभीर प्रशासनिक प्रश्न है। खास बात यह है कि सीहोर राजधानी भोपाल से सबसे नजदीकी जिलों में है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य शिक्षा केंद्र के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इतने महत्वपूर्ण जिले की व्यवस्था पर क्यों नहीं है? विभागीय नियमों के अनुसार पात्रता, परीक्षा और पदस्थापना की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाना जरूरी है।

हरित शहरों की दिशा में माली कर्मचारियों का कौशल संवर्धन

पौधों के जीवन रक्षण और हरित संवर्धन में प्रशिक्षित मालियों की भूमिका अहम : आयुक्त भोंडवे

भोपाल, देशबन्धु। शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने और लगाए गए पौधों को सुरक्षित रखकर उन्हें वृक्ष का स्वरूप देने में प्रशिक्षित माली कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधरोपण तभी सार्थक होगा, जब प्रत्येक पौधे की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल कर उसे स्वस्थ और विशाल वृक्ष बनाया जाए। यह बात नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने भौंरी स्थित सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय माली प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर कही।

1 और 2 सितंबर को हुई कार्यशाला में प्रदेश के सभी 10 संभागों से करीब 215 से 220 माली कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण में नर्सरी प्रबंधन, भू-दृश्य सज्जा, उद्यान की रूपरेखा तैयार करने, पौधरोपण की आधुनिक तकनीक, पौध पोषण, मिट्टी प्रबंधन, सिंचाई तथा कटाई-छंटाई सहित पौधों के नियमित रखरखाव की जानकारी दी गई। 'नमो हरित-नगर योजना' के तहत व्यवस्थित पौधरोपण के जरिए शहरों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

आयुक्त भोंडवे ने बताया कि प्रदेश में 'अमृत हरित महाभियान' के तहत अब तक 51 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि तभी स्थायी मानी जाएगी, जब लगाए गए पौधों का संरक्षण सुनिश्चित हो और वे पेड़ बनें। इसके लिए प्रशिक्षित माली कर्मचारियों की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है। 'नमो हरित-नगर योजना' और 'अमृत हरित महाभियान' के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के नगरों में टिकाऊ हरित क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।

कार्यशाला में सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी अशोक मिश्रा, उदय रोमन, सर्वेश तिवारी और भू-दृश्य वास्तु विशेषज्ञ रूपम मिश्रा ने प्रशिक्षण दिया। समापन पर प्रतिभागियों ने अपने-अपने नगरीय निकायों में सीखी तकनीकों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षण से पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने और शहरों के पार्कों व हरित पट्टियों के बेहतर रखरखाव में मदद मिलेगी।

राजधानी

सार-समाचार

नाला निर्माण में उदासीनता, कार्यपालन यंत्री बृजेश निलंबित

भोपाल, देशबन्धु । सौंपे गए कार्य में लापरवाही और उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर नगर निगम प्रशासन ने कार्यपालन यंत्री बृजेश कौशल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत की गई। निगम के अनुसार जोन क्रमांक 16 के शिव नगर में नाला निर्माण का कार्य 10 मई 2023 से 9 मई 2024 तक पूरा किया जाना था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा रहा। कार्य पूरा कराने के लिए कौशल को पहले कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने 10 और 24 अगस्त को जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया था।

103 स्थानों से जल के नमूने लिए, 7 पाइपलाइन रिसाव सुधारे

भोपाल, देशबन्धु। नगर निगम ने शहरवासियों को स्वच्छ और जीवाणुरहित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल गुणवत्ता की जांच और पाइपलाइनों के रिसाव सुधारने की कार्रवाई जारी रखी। बुधवार को निगम के जलकार्य विभाग के अमले ने शहर के 103 स्थानों से पानी के नमूने एकत्र किए। इन नमूनों की जांच निगम की 8 परीक्षणशालाओं में की जा रही है। अब तक कुल 29,146 जल नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के 13,335 नमूने शामिल हैं। निगम के कर्मचारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 7 स्थानों पर पाइपलाइनों के रिसाव भी सुधारे।

राजधानी की स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था बनेगी अन्य शहरों के लिए मिसाल

भोपाल, देशबन्धु। शहर में आधुनिक और नकदरहित वाहन पार्किंग व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने एमपी नगर और न्यू मार्केट की बहुमंजिला पार्किंग में नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें फास्टैग, यूपीआई और मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से पार्किंग शुल्क जमा करने की सुविधा दी जा रही है। निगम ने 9 जुलाई से शहर की पांच बहुमंजिला पार्किंग में नकद भुगतान पर रोक लगाकर डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दी है। नई व्यवस्था में पार्किंग के प्रवेश और निकास द्वार पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगाए गए हैं। कैमरा वाहन की नंबर प्लेट पहचानकर फास्टैग के माध्यम से प्रवेश दर्ज करता है और पार्किंग का अभिलेख स्वत: तैयार हो जाता है। वाहन के बाहर निकलने पर भी उसकी पहचान कर निर्धारित शुल्क फास्टैग से जमा हो जाता है। फास्टैग में परेशानी होने पर क्यूआर संकेतक और यूपीआई से भुगतान की वैकल्पिक सुविधा भी उपलब्ध है।

वन समिति की बैठक को लेकर जनप्रतिनिधि नाराज

3 घंटे इंतजार करते रहे जिला पंचायत सदस्य, नहीं पहुंचे वन विभाग के अधिकारी

भोपाल, देशबन्धु। जिला पंचायत भोपाल में बुधवार को वन स्थायी समिति की प्रस्तावित बैठक अधिकारियों की गैरमौजूदगी के कारण नहीं हो सकी। बैठक दोपहर 3 बजे निर्धारित थी, लेकिन शाम 6 बजे तक वन विभाग का कोई अधिकारी जिला पंचायत के सभाकक्ष में नहीं पहुंचा। बैठक के लिए पहुंचे समिति सदस्य विनय मेहर ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे जनप्रतिनिधियों की अनदेखी बताया।

मेहर निर्धारित समय पर जिला पंचायत पहुंचे और अधिकारियों के आने का इंतजार करते रहे। तीन घंटे बाद भी जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि बैठक निरस्त किए जाने की जानकारी समिति सदस्यों को पहले से नहीं दी गई। बैठक आयोजित करने के लिए विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था, लेकिन निरस्त करने के संबंध में न तो कोई पत्र भेजा गया और न ही मौखिक सूचना दी गई।

मेहर ने आरोप लगाया कि वन स्थायी समिति की बैठक वर्ष में चार से पांच बार होनी चाहिए, लेकिन लंबे समय से नियमित बैठकें नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह के बाद बुधवार को बैठक तय की गई थी। इसके बावजूद अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि विभाग बैठक आयोजित नहीं करना चाहता। समिति सदस्य ने वन मंडलाधिकारी लोकप्रिय भारती से भी मामले को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से शिकायत की जाएगी और बैठक नहीं होने के कारणों की जानकारी मांगी जाएगी।

बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज मेहर ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वे बैठक में शामिल होने के लिए घर से भोजन लेकर आए थे और अधिकारियों के इंतजार में वहीं भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को बैठक निरस्त होने की सूचना तक नहीं देना उचित नहीं है।

युवा शक्ति को सही दिशा और दृढ़ संकल्प की जरूरत, हर संकल्प सफलता की राह खोलता है: राज्यमंत्री

भोपाल, देशबन्धु। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि जीवन में लिया गया प्रत्येक सकारात्मक संकल्प व्यक्ति को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण की मजबूत आधारशिला है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत, अनुशासन, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

राज्यमंत्री गौर बुधवार को बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आयोजित दीक्षारंभ समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने समारोह का शुभारंभ करते हुए संस्थान में प्रवेश लेने वाले नवागत विद्यार्थियों को सफल, सुखद और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज विद्यार्थियों के जीवन में एक नए सफर की शुरुआत हुई है। यह समय केवल पढ़ाई तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि अपने सपनों को आकार देने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं में उत्साह, क्षमता और नई चुनौतियों का सामना करने का साहस है। तेजी से बदलती दुनिया में वही युवा आगे बढ़ेगा, जो परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने के साथ अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। निरंतर मेहनत, अनुशासन और धैर्य ही व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। राज्यमंत्री ने कहा कि आज का युवा बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखता है। देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता युवाओं में है, जरूरत केवल सही दिशा, दृढ़ संकल्प और लगातार प्रयास की है। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न रखें, बल्कि परिवार, समाज, संस्थान और देश के विकास में भी योगदान दें। श्रीमती गौर ने कहा कि उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने, शिक्षकों का मार्गदर्शन लेने और अपने व्यवहार में अनुशासन बनाए रखने की सीख दी।

परमाणु विज्ञानिक ही नहीं जन-विज्ञान आंदोलन के प्रणेता है परमेश्वरन : बेहार

भोपाल, देशबन्धु । मध्य प्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति, एकलव्य और मध्य प्रदेश विज्ञान सभा के संयुक्त तत्वावधान में प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक एवं जन-विज्ञानी डॉ. एम. पी. परमेश्वरन की स्मृति में त्रिलंगा स्थित ज्ञान विज्ञान समिति परिसर में एक गरिमामय स्मृति-सभा आयोजित की गई।

सभा की अध्यक्षता शरद चंद्र बेहार और डॉ. अनिता रामपाल ने की। इस दौरान वक्ताओं ने अक्षर, साक्षरता और विज्ञान को आम जनमानस तक पहुँचाने में डॉ. परमेश्वरन के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया।

अध्यक्षता करते हुए शरद चंद्र बेहार और डॉ. अनिता रामपाल ने कहा कि डॉ. परमेश्वरन ने केवल विज्ञान को प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक बदलाव और तार्किक चेतना का सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने देश में साक्षरता आंदोलन और जन-विज्ञान अभियानों को जो दिशा दी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेगी।

स्मृति-सभा को संबोधित करते हुए श्याम बोहरे, मनोज कुलकर्णी, अंजलि नरोन्हा और डॉ. ईश्वर सिंह दोस्त ने उनके साथ बिताए संस्मरण साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में प्रतिष्ठित करियर होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन आम जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए समर्पित कर दिया। राजू कुमार, शिव नारायण, आशा मिश्रा और एस. आर. आज़ाद ने डॉ. परमेश्वरन के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका सपना एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ तर्क, समता और वैज्ञानिक समझ हर नागरिक के जीवन का हिस्सा हो। सामाजिक बदलाव के लिए विज्ञान के विचार को उन्होंने धरातल पर उतार कर दिखाया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत विभूति को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए रास्ते पर जन-विज्ञान आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

सीलिंग कार्रवाई के विरोध में कोलार बंद

भोपाल, देशबन्धु। भोपाल में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में बुधवार को कोलार क्षेत्र का बाजार पूरी तरह बंद रहा। कोलार तिराहे से गोल जोड़ तक अधिकांश प्रतिष्ठानों के शटर नहीं खुले। बड़े प्रतिष्ठानों के साथ डी-मार्ट, वी-मार्ट, विशाल मेगामार्ट और मंदाकिनी चौराहा व डी-मार्ट चौराहे की शराब दुकानें भी बंद रहीं। हालांकि चिकित्सा दुकानों और पेट्रोल पंपों को बंद से छूट दी गई।

बंद के दौरान व्यापारियों ने दोपहर में प्रतीकात्मक रूप से कारोबार की अर्थी सजाकर कंधा दिया और नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। कोलार व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि कार्रवाई से व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। महासंघ ने प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार कर व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की।

व्यापारियों के विरोध के बीच मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी सहित भोपाल के कई जनप्रतिनिधियों ने बुधवार सुबह मुख्यमंत्री यादव से मुलाकात की। बताया गया कि बैठक में भोपाल के मास्टर प्लान, मिश्रित भूमि उपयोग और भूमि विकास से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा हुई। इससे मास्टर प्लान की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।व्यापारियों की मांग है कि मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाए और रहवासी क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग का प्रावधान किया जाए।

सिद्धांता अस्पताल का पंजीयन और लाइसेंस निरस्त, जांच में मिलीं 19 गंभीर खामियां

भोपाल, देशबन्धु। शिवाजी नगर स्थित सिद्धांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का पंजीयन और अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की जांच में इमरजेंसी, गहन चिकित्सा इकाई, डायलिसिस, एक्स-रे, पैथोलॉजी और अग्नि सुरक्षा सहित 19 गंभीर कमियां सामने आईं।

जांच में इमरजेंसी में पर्याप्त उपकरण नहीं मिले। वहां एक रक्तचाप जांच यंत्र और एक ऑक्सीजन सिलेंडर पाया गया, जबकि दुर्घटना उपचार क्षेत्र में क्रैश कार्ट बंद मिली। डायलिसिस इकाई में चार बिस्तरों के मुकाबले दो तकनीशियन मिले। संक्रमण से बचाव के लिए सीरो-पॉजिटिव मरीजों की अलग व्यवस्था और जरूरी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं थे। गहन चिकित्सा इकाई में संक्रमित मरीजों के लिए बने कक्षों में असंक्रमित मरीज भर्ती पाए गए। एक्स-रे जांच के दौरान सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल में भी कमी मिली। अग्नि सुरक्षा जांच में वैकल्पिक निकास और पूर्व में दिए गए सुझावों के अनुपालन से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

सेडमेप के खिलाफ न्यायालय में चालान

भोपाल, देशबन्धु। जयप्रकाश चिकित्सालय (1250) परिसर में बायो मेडिकल कचरा अन्य कचरे के साथ खुले में पड़ा मिलने पर नगर निगम ने अस्पताल की हाउस कीपिंग संस्था सेडमेप के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है। निगम अधिकारियों ने अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संजय जैन और सेडमेप के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया। अधीक्षक के दूरभाष से सूचना देने के बावजूद संस्था का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा और न जुर्माना जमा कराया। इसके बाद निगम ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्रवाई की।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार आत्मज कन्हैया लाल अहिरवार आयु 34 वर्ष, निवासी-36, वार्ड नं. 8, मडना सुल्तान, भुगावली, पथरिया जोगन जिला सागर म.प्र. का हूँ। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम SAVING दर्ज हो गया है जो कि गलत है मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम शिवांश अहिरवार (Shivansh Ahirwar) है जोकि उससके शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज होने से प्रमाणित है ।मैं अपने पुत्र का वास्तविक सही नाम आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। भविष्य में मेरे पुत्र को शिवांश अहिरवार के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- SAVING

नया नाम - शिवांश अहिरवार (Shivansh Ahirwar)

न्यायालय तहसीलदार राजधानी परियोजना टी टी नगर भोपाल

(शेड नं. 06 बारह दफ्तर जवाहर चौक भोपाल)

प्र.क्र. 0201/1-6/2026-27

इश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका सोनल कठाने पुत्री श्री अरविन्द नाथ व्यास निवासी-ए-65, कमला नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल द्वारा ग्राम कोटरा सुल्तानाबाद स्थित कमला नगर भूखण्ड क्रमांक ए-65, क्षेत्रफल 2300 वर्गफिट का रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

इस संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकरण में 07 दिवस के भीतर इस न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि व्यतीत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
टी.टी.नगर वृत्त भोपाल

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रॉपर्टी आई. डी. नं. 2330200123, आवेदन क्रमांक-12567 आवेदन दिनांक 03.07.2026

क्रमांक 2347 / राजस्व / भोविप्रा /26 भोपाल दिनांक: 31.08.2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की एम.पी. नगर जोन-1 योजना में स्थित भूखण्ड क्रमांक 241 एवं 242 पर निर्मित कार्यालयीन प्रकोष्ठ क्रमांक 316 प्रथम तल जिसका क्षेत्रफल 15.79 वर्गमीटर अर्थात 170 वर्गफुट श्री आर.एच. शाह आ. श्री हिरालाल शाह के नाम पर अंकित है। जिनके द्वारा उक्त प्रकोष्ठ का विक्रय मेसर्स प्रीमियम ट्रांसपोट लिमि. डायरेक्टर श्री सुरेश गुप्ता के नाम पर करने हुये उसकी राजिस्ट्री दिनांक 24.03.1999 को उनके नाम पर करा दी, क्रेता द्वारा उक्त कार्यालयीन प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने नाम पर नही कराया गया एवं उनके द्वारा प्रकोष्ठ की राजिस्ट्री दिनांक 27.06.2012 श्री मोहन अग्रवाल आ. श्री बी.एल. अग्रवाल एवं श्रीमती मिथलेश अग्रवाल पत्नी श्री मोहन लाल अग्रवाल के नाम पर करा दी, अब श्री मोहन लाल अग्रवाल एवं श्रीमती मिथलेश अग्रवाल द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र शपथ पत्र आदि अभिलेख संलग्न कर प्रकोष्ठ का नामांतरण अपने संयुक्त नाम पर किये जाने का निवेदन किया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य / दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति / दावा प्रस्तुत करे ।उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा / आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर

क्रं./ जलप्रदाय/न.नि./2026/08 सागर दिनांक 02.09.2026

ऑनलाईन निविदा सूचना

नगर पालिक निगम सागर के अंतर्गत जल प्रदाय विभाग में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये पाईप लाईन, फिटिंग सामग्री, पंप इत्यादि सामग्री प्रदाय करने हेतु इच्छुक डीलर / निर्माता अपनी दरें ऑनलाईन माध्यम से नियत तिथि तक जमा कर सकते हैं। कार्य का विवरण निम्नानुसार है

क्रं.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ई.एम. डी.	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_533331_1 03.09.2026	जल प्रदाय विभाग में पाईप लाईन विस्तार, लीकेज सुधार कार्य, हैण्डपंप मरम्मत तथा नलकूप मरम्मत व फिटिंग सामग्री, पंप इत्यादि सामग्री प्रदाय करने का कार्य।	वित्तीय वर्ष 2026-27	5,000/- 50000/-	05.10.2026 शाम 05.30 तक

नोट:- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑन लाईन https://mptenders.gov.in की बेबसाईट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम सागर

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम स्नेहा शंकरलाल मदनानी पिता शंकरलाल (Sneha Shankarlal Madnani D/o Shankarlal) था जो कि मेरी अंकसूची में अंकित है । मेरा विवाह श्री अभिषेक मेरानी से हो जाने के बाद अब मेरा नाम मायशा मेरानी हो गया है । विवाह उपरांत अब मुझे मायशा मेरानी पत्नी अभिषेक मेरानी (Mayesha Merani W/o Abhishek Merani) नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी दस्तावेजों में यही नाम मान्य किया जावे ।

पुराना नाम:
स्नेहा शंकरलाल मदनानी पिता शंकरलाल (Sneha Shankarlal Madnani D/o Shankarlal)

नया नाम:
मायशा मेरानी पत्नी अभिषेक मेरानी (Mayesha Merani W/o Abhishek Merani)

देशबन्धु

भोपाल, गुरूवार, 3 सितम्बर 2026

संस्थापक-संपादक : स्व. मायाराम सुरजन

पत्रकारों पर नया हमला

पश्चिम बंगाल के प्रमुख बंगाली समाचार पत्र आनंदबाजार पत्रिका इस समय भाजपा और शुभेन्दु अधिकारी सरकार के निशाने पर आ गया है। मंगलवार को अखबार के दफ्तर के बाहर भगवा रंग के कपड़े पहने कुछ गुंडों ने दीवार को भगवा रंग पोत दिया और यह सब जब हो रहा था तो कोलकाता पुलिस वहीं मौजूद थी। घटना के जो वीडियो सामने आए हैं, उसमें यह गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने लिखा है कि बंगाल अंधकार युग में चला गया है। वाकई जो माहौल इस समय बंगाल में बना दिया गया है, वह किसी अंधेरे से कम नहीं है।

मई में चुनाव जीतने के बाद से भाजपा एकदम मदांध होकर व्यवहार कर रही है। टीएमसी नेताओं को तो लगातार निशाना बनाया ही जा रहा है, इसके अलावा हर उस आवाज को कुचलने की कोशिश हो रही है जो भाजपा सरकार के विरोध में उठे।

20 अगस्त को ही शुभेन्दु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी में लाल सलाम किशनजी के नारे दीवारों पर लिखे होने का विरोध करते हुए कहा कि नारों के साथ बहुत कुछ मिटा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के नारे लगाने वाले तत्वों को 'घर के कचरे की तरह साफ' कर देना चाहिए। शुभेन्दु अधिकारी के बयान के बाद ही यूनिवर्सिटी की दीवारों पर रंगाई-पुताई होने लगी और प्रशासन ने कहा कि यह सफाई करने के लिए हो रहा है। जबकि माकपा और एसएफआई जैसे संगठनों का कहना है कि यह असहमति की आवाज दबाने की कोशिश है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोशिश केवल यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रही, बल्कि स्वतंत्र पत्रकारिता को कुचलने तक पहुंच चुकी है।

जादवपुर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी स्टूडेंट्स यूनियन और एबीवीपी के बीच हुई झड़पों पर आनंद बाजार पत्रिका ने भगवा गुंडागर्दी शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इस शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए अखबार के संपादकीय विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त को शास्त्री महाराज नामक व्यक्ति ने कोलकाता में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि 'भगवा गुंडागर्दी' शब्द का इस्तेमाल जानबूझ कर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में अशांति फैलाने के उद्देश्य से किया गया। इसके आधार पर 28 अगस्त को पुलिस ने आनंदबाजार पत्रिका के संपादकीय विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

एफआईआर में आनंदबाजार पत्रिका की संपादक ईशानी दत्ता रॉय, चीफ रिपोर्टर सोमा मुखर्जी और संपादकीय टीम के अन्य सदस्यों के नाम शामिल किए गए हैं। शिकायत में मांग की गई है कि पुलिस यह जांच करे कि विवादित शब्द का सुझाव किसने दिया, शीर्षक किसने मंजूर किया और संपादन प्रक्रिया में कौन-कौन शामिल था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह शब्द इस्तेमाल किया। इसके बाद भगवा कपड़े पहने कई लोग मंगलवार दोपहर आनंदबाजार पत्रिका के कार्यालय के बाहर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने 'आनंदबाजार पत्रिका हाय-हाय' और 'भगवा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा' जैसे नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने अखबार दफ्तर की दीवारों पर भगवा रंग पोत दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद अखबार प्रबंधन ने दीवारों को दोबारा सफेद रंग से रंगवा दिया। हालांकि पुलिस ने इस घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यह भी साफ़ नहीं है कि दीवारों पर रंग पोतने वाले लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है या नहीं।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी आनंदबाजार पत्रिका से 24 घंटे के भीतर 'भगवा गुंडागर्दी' शीर्षक के लिए माफी मांगने को कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अखबार माफी नहीं मांगता तो भगवा पहनने वाले लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अखबार ने माफी जारी नहीं की। इसके बाद कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। एक ही घटना की ये सारी कड़ियां आपस में जिस तरह जुड़ रही हैं, उससे जाहिर है कि सत्ता के समर्थन के बिना अखबार के दफ्तर पर पहुंच कर गुंडागर्दी करने और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर नहीं किया गया है। बहरहाल यह मामला बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंचा, जहां पत्रकारों की तरफ से उपस्थित हुए सीनियर एडवोकेट एस.एन. मुखर्जी ने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि अखबार में भगवा गुंडागिरी शब्द के इस्तेमाल के बाद पत्रकारों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए और उन्हें तत्काल राहत की जरूरत है। लेकिन जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए विशेष रूप से तारीख तय करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पहले एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की जाए। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में अदालत का क्या फैसला रहता है।

इधर पत्रकार संगठनों ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए एफआईआर तुरंत वापस लेने की मांग की है। इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स और प्रेस एसोसिएशन ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पत्रकारों का काम तथ्यों को सामने लाना है। कई बार रिपोर्टिंग या इस्तेमाल किए गए शब्द कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन यही स्वतंत्र पत्रकारिता और लोकतंत्र की बुनियाद है।

प्रेस संगठनों ने शिकायत में यह मांग किए जाने पर भी आपत्ति जताई कि विवादित शब्द का सुझाव किसने दिया, उसे किसने मंजूर किया और शीर्षक तय करने में कौन-कौन शामिल था। उनका कहना है कि इस तरह संपादकीय प्रक्रिया में शामिल पत्रकारों और संपादकों की पहचान मांगना सीधे तौर पर पत्रकारों को निशाना बनाने जैसा है। संगठनों ने इसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का संरक्षण जरूरी है, न कि उसे कानूनी कार्रवाई के जरिए दबाने की कोशिश।

लेकिन प्रेस संगठनों को भी अब बदले हालात पर गौर करना होगा कि नैतिकता का हवाला देकर अगर लोकतंत्र मजबूत बनाया जा सकता तो आज ऐसी नौबत ही नहीं आती। हाल ही में राजदीप सरदेसाई को दिमागी नक्सल भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया था। उसके चंद दिनों बाद अब पत्रकारों पर एफआईआर हो रही है। पिछले 12 सालों में ऐसे सैकड़ों मामले हो चुके हैं जिससे भारत की प्रेस स्वतंत्रता बाधित हुई है। तो पत्रकारों को भी अब नजर और नजरिए का फर्क समझ कर जुबानी जमाखर्च से आगे बढ़कर मजबूत एकता दिखानी होगी।

छवियों में कैद मोदी विदेश नीति

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के बयानों और व्यवहार को लेकर फिर सुर्खियां बन रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बनाई विदेश नीति में कैमरे में कैद छवियों को अहम बना दिया है। अब तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबकी विदेश यात्राओं में इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि भारत के हित में कौन से समझौते हुए, वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति मजबूत करने के लिए किन देशों के साथ उसके मैत्री संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, गुटनिरेपक्षता के सिद्धांत को इन संबंधों में कितनी तरजीह दी जा रही है। लेकिन अब ऐसे सारे सवाल उठते ही नहीं। बेशक व्यापार और रक्षा समझौतों की बात होती है, लेकिन उसके अलावा खबरों में यही दिखाया जाता है कि नरेन्द्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, गले मिले, किसके साथ एक कार में सफर किया, कौन से उपहार दिए या लिए और हां इन सबसे पहले यह बताया जाता है कि कौन से देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया। गोया, यह भारत के प्रधानमंत्री की नहीं, नरेन्द्र मोदी की विशेष उपलब्धि हो।

बहरहाल, बिश्केक में भी नरेन्द्र मोदी के अन्य नेताओं के साथ मिलने और बात करने की तस्वीरें, वीडियो आते रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेन्द्र मोदी ने एक कार में सफर किया, उसकी तस्वीरें सामने आईं। फिर एक वीडियो आया जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन साथ आते हैं और सामने से नरेन्द्र मोदी जिनपिंग से हाथ मिलाते हैं और उसी समय दूसरे हाथ से पुतिन का हाथ भी थामते हैं। विश्व की दो महाशक्तियों के साथ एक हाथ मिलाते नरेन्द्र मोदी काफी शक्तिशाली प्रधानमंत्री लग सकते हैं। लेकिन ये शक्ति तब भी नजर आनी चाहिए जब अरुणाचल प्रदेश समेत कई हिस्सों में चीन अपनी घुसपैठ करता है या फिर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मदद करता है। एक समूह चित्र खिंचवाने से पहले का भी वीडियो आया, जिसमें नरेन्द्र मोदी पुतिन से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि पुतिन उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पुतिन उन्हें दूसरी तरफ कर खुद लगभग केंद्र में आ जाते हैं, फिर उनके बगल में आकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को खड़ा कर दिया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह पुतिन के बाजू में खड़े किए गए और नरेन्द्र मोदी लगभग किनारे क्यों खड़े किए गए, यह क्रम किस आधार पर तय हुआ, यह विदेश मंत्रालय ही बेहतर बता सकेगा। हालांकि इस समूह चित्र को जब पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया और लिखा 'प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ 1 सितंबर 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट समिट में राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक ग्रुप फोटो में।' फिर शाहबाज शरीफ ने पूरी निर्लज्जता के साथ अपने एक्स हैंडल पर उसी फोटो को शेयर किया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर को वैसे ही शेयर किया, जैसे वह खींची गई थी। मोदी के हैंडल से शेयर हुई फोटो में शाहबाज शरीफ भी हैं। अच्छा है कि भारत ऐसे ओछेपन से अब तक बचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार लगातार इसी तरह का ओछापन दिखाती रही है और अब मक्का रक्षा समझौते के बाद उसके ऐसे दुस्साहस कुछ और बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआती तीन सालों के लिए जिम्मेदारी पाकिस्तानी के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को ही मिली है।

गौरतलब है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (नाटो) की तर्ज पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त 2026 को एक त्रिपक्षीय सामूहिक रक्षा समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर बाहरी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा (जो नाटो के आर्टिकल-5 की तरह है)। इसे 'इस्लामिक नाटो' भी कहा जा रहा है। इस समझौते का दायरा बढ़ाए जाने की संभावना है और संभव है कि निकट भविष्य में बांग्लादेश भी इसका सदस्य बन जाए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने दावा किया है कि मक्का समझौता किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होगी और अनिश्चितता में कमी आएगी।

हर संगठन अपनी स्थापना को लेकर नेक इरादे ही प्रकट करता है, लेकिन उसका विस्तार या प्रभाव दिखाना होता है, तो फिर उसमें उन देशों को निशाने पर लिया जाता है, जिनसे हित टकराते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले चार सालों से चल रही जंग इसका उदाहरण है। नाटो देश यूक्रेन को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। यूक्रेन भी नाटो का सदस्य होना चाहता है, लेकिन रूस इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि एक बार नाटो का प्रभाव उसकी सीमाओं तक आ गया तो फिर शीतयुद्ध के दौर जैसे हालात बन जाएंगे। यूक्रेन जिस तरह बार-बार अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से सहानुभूति बटोरते हुए युद्ध में टिके रहने के लिए उनसे सामरिक मदद मांग रहा है, यह इस बात का उदाहरण है कि रूस केवल यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, पर्दे के पीछे नाटो की शक्ति भी काम कर रही है। इस मिसाल को देखते हुए मक्का समझौते के बाद भारत को विशेष तौर पर सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ही हमने देखा है कि कैसे अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच दखलंदाजी की और पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया। अब क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के नाम पर अगर पाकिस्तान फिर किसी अनावश्यक संघर्ष को बढ़ाएगा तब भारत केवल पाकिस्तान से मुकाबला नहीं करेगा, हो सकता है पीछे से सऊदी अरब और तुर्की भी साथ रहें।

हर संगठन अपनी स्थापना को लेकर नेक इरादे ही प्रकट करता है, लेकिन उसका विस्तार या प्रभाव दिखाना होता है, तो फिर उसमें उन देशों को निशाने पर लिया जाता है, जिनसे हित टकराते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले चार सालों से चल रही जंग इसका उदाहरण है। नाटो देश यूक्रेन को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं।

भारत के लिए विदेश नीति की चुनौतियां अब पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद की जाती है कि वे फोटो-वीडियो, हाथ मिलाने-गले मिलने पर ध्यान देने की जगह इन चुनौतियों की जटिलताओं को समझें। अभी बिश्केक में नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से अपील की कि वे यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस के युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। मोदी ने एंडलेस वॉर की जगह वॉर के एंड पर जोर दिया। ऐसी लफ्फाजी से बेहतर है कि वे ठोस तथ्यों पर बात करें। यह सही है कि चार सालों से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसे मोदी क्यों एंडलेस यानी अंतहीन बता रहे हैं। इसका मतलब वे रूस पर दोषारोपण कर रहे हैं कि वह युद्ध खत्म नहीं कर रहा। इससे पहले भी मोदी पुतिन से कई बार इसी तरह की अपील कर चुके हैं, हालांकि उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बल्कि 2024 में जब मोदी यूक्रेन गए और वहां जेलेंस्की से मुलाकात की, तो इसके करीब ढाई महीने बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को रूस में पुतिन के सामने बैठकर इस मुलाकात पर सफाई पेश करनी पड़ी थी।

भारत वैश्विक शांति का हमेशा से पक्षधर रहा है। प.नेहरू ने गुटनिरपेक्ष और पंचशील का सिद्धांत शांति के मद्देनजर ही दिया था। लेकिन खुद मोदी सरकार ने विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को गौण बना दिया है, यह जाहिर है। इसलिए अगर मोदी पुतिन को युद्ध खत्म करने कह सकते हैं, तो यही रवैया उन्हें इजरायल और अमेरिका के साथ भी अपनाना चाहिए। फिलीस्तीन पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने न केवल चुप्पी बरती बल्कि मोदी इजरायल जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, उनसे सम्मान ग्रहण किया, आतंकवाद के खात्मे की बात की, तो यह सब गज़ा में चल रहे नरसंहार को समर्थन जैसा ही है। क्योंकि इजरायल के लिए आतंकवाद का दूसरा नाम हमास है। इसके बाद ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले में भी मोदी ने प्रतिक्रिया देने में न केवल देर की, बल्कि इस तरह प्रतिक्रिया दी कि कहीं से इजरायल और अमेरिका की हरकत का विरोध नजर नहीं आया। अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बावजूद नरेन्द्र मोदी ने अफसोस जाहिर नहीं किया। तो रूस से अगर मोदी कह रहे हैं कि यूक्रेन के साथ युद्ध को खत्म किया जाए, तो यही बात उन्हें खुल कर इजरायल और अमेरिका को भी कहनी होगी। वैश्विक मंच पर भारत का इकबाल इसी तरह नजर आएगा।

बच्चों की डिजिटल दुनिया कितनी सुरक्षित

■ राजु कुमार

भारत में बच्चों की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत से लेकर अपनी बात कहने तक इंटरनेट अब बच्चों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इंटरनेट पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी के साथ उनके सामने खतरे भी बढ़े हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ब्लैकमेलिंग, तस्वीरों के दुरुपयोग, निजता के उल्लंघन और ऑनलाइन यौन शोषण जैसे अपराध बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के क्राई द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, 2017 से 2024 के बीच बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराधों में करीब 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी अवधि में बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़े अपराधों में 157 गुना वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि 2023 के उच्चतम स्तर की तुलना में 2024 में बच्चों के खिलाफ दर्ज साइबर अपराधों में करीब आठ प्रतिशत की कमी आई है।

भारत में 18 साल से कम उम्र के करीब 11.3 करोड़ बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में उनकी हिस्सेदारी करीब 14 प्रतिशत है। वहीं, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकानॉमिक रिसर्च की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 13 से 16 वर्ष की उम्र के 65.3 प्रतिशत बच्चों की मोबाइल तक पहुंच है, 37.8 प्रतिशत इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और 21.3 प्रतिशत सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। महानगरों में 73.1 प्रतिशत बच्चों की मोबाइल तक पहुंच है और 49.3 प्रतिशत इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जबकि कम विकसित गांवों में ये आंकड़े क्रमशः 64.2 और 33.3 प्रतिशत हैं।

ऑनलाइन अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच दुनिया के कई देशों ने बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मंचों की जिम्मेदारी तय करने के सख्त कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर 2025 से प्रमुख सोशल मीडिया मंचों के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को खाता बनाने या रखने से रोकने के लिए उचित कदम उठाना कानूनी जिम्मेदारी बन गया है। इसकी जिम्मेदारी बच्चे या माता-पिता के बजाय ऑनलाइन मंचों पर डाली गई है।

ब्रिटेन के ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम में ऑनलाइन सेवाओं के लिए बच्चों के सामने मौजूद जोखिमों का आकलन और उनसे बचाव के उपाय जरूरी किए गए हैं। नुकसानदेह सामग्री तक बच्चों की पहुंच रोकने के लिए उम्र सत्यापन के उपाय भी किए गए हैं। इसी तरह यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम में बच्चों की निजता और सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मंचों की जवाबदेही तय की गई है, जिसमें बच्चों के खातों को सामान्य रूप से निजी रखने और हानिकारक सामग्री की सिफारिश करने वाली स्वचालित प्रणालियों पर नियंत्रण जैसे उपाय शामिल हैं।

भारत में भी बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67बी बच्चों से जुड़ी यौन सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन या प्रसारण सहित कई गतिविधियों को दंडनीय बनाती है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 ऑनलाइन मंचों पर कुछ जिम्मेदारियां डालते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में बच्चों के व्यक्तिगत डेटा की विशेष सुरक्षा के साथ उनकी ऑनलाइन गतिविधियों और व्यवहार की निगरानी तथा उन्हें लक्षित कर विज्ञापन दिखाने पर रोक का प्रावधान है। हालांकि इसके प्रमुख प्रावधान अभी पूरी तरह प्रभावी नहीं हुए हैं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर व्यापक व्यवस्था अभी विकसित हो रही है।

कानून और तकनीकी उपाय जरूरी हैं, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का सवाल केवल उम्र सत्यापन या किसी वेबसाइट को रोकने तक सीमित नहीं है। बच्चे इंटरनेट पर किससे बात कर रहे हैं, क्या साझा कर रहे हैं, किन संपर्क सूत्रों पर जा रहे हैं और परेशानी होने पर किससे मदद मांग सकते हैं, इसकी समझ भी उतनी ही जरूरी है। कई बार बच्चे किसी गलत ऑनलाइन अनुभव की जानकारी इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि परिवार उन्हें ही दोषी ठहराएगा, उनका फोन छीन लिया जाएगा या उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाएगा। ऐसे में परिवारों और स्कूलों के सामने चुनौती निगरानी बढ़ाने के साथ ऐसा भरोसेमंद माहौल बनाने की भी है, जिसमें बच्चा किसी परेशानी के बारे में बिना डर के बता सके।

इन्हीं परिस्थितियों में बच्चों के मुद्दे पर कार्यरत चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस बनाने के लिए देशव्यापी 'टिंग टोंग' अभियान की शुरुआत की है। अभियान का मूल संदेश ऑनलाइन कुछ भी करने से पहले एक पल रुक कर सोचने की आदत विकसित करना है। क्राई की मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूजा मारवाह ने कहा, 'आज बच्चे दो दुनियाओं में बड़े हो रहे हैं—एक भौतिक दुनिया और दूसरी डिजिटल दुनिया। जिस तरह हम अपने घरों, स्कूलों और आस-पड़ोस को सुरक्षित बनाने के लिए काम करते हैं, उसी तरह हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे जिस डिजिटल स्पेस का हिस्सा हैं, वह सुरक्षित, समावेशी हो और उनके अधिकारों का सम्मान करता हो। ऑनलाइन सुरक्षा अब केवल तकनीक का मुद्दा नहीं रह गया है; यह मूलरूप से बाल सुरक्षा का मुद्दा है। इस अभियान के जरिए हम चाहते हैं कि हम सभी अपने व्यवहार में एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। ऑनलाइन कुछ भी क्लिक करने, किसी पर भरोसा करने, कुछ शेयर करने या पोस्ट करने से पहले बस एक पल रुकना बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।'

बच्चों को सुरक्षित रखने का समाधान न तो उन्हें डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूर करने में है और न ही सारी जिम्मेदारी बच्चों और उनके माता-पिता पर डाल देने में। इंटरनेट अब शिक्षा, सूचना, रचनात्मकता और सामाजिक भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें सरकार स्पष्ट और प्रभावी नियम बनाए, तकनीकी कंपनियां अपने ऑनलाइन मंचों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी लें।

दरअसल, बच्चों को सुरक्षित रखने का समाधान न तो उन्हें डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूर करने में है और न ही सारी जिम्मेदारी बच्चों और उनके माता-पिता पर डाल देने में। इंटरनेट अब शिक्षा, सूचना, रचनात्मकता और सामाजिक भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है। जरूरत ऐसी व्यवस्था की है जिसमें सरकार स्पष्ट और प्रभावी नियम बनाए, तकनीकी कंपनियां अपने ऑनलाइन मंचों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी लें, स्कूल डिजिटल सुरक्षा को बच्चों की शिक्षा का हिस्सा बनाएं और परिवार बच्चों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें। बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आजादी और डिजिटल दुनिया के खतरों से सुरक्षा—दोनों को साथ लेकर चलना ही आने वाले समय की बड़ी बाल अधिकार चुनौती है।

आपके पत्र

मक्का समझौते से बदलता पश्चिम एशिया का सुरक्षा समीकरण

पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की राजनीति में इन दिनों एक नया सुरक्षा समीकरण आकार लेता दिखाई दे रहा है। तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के बाद इस्तांबुल में हुई पहली रणनीतिक बैठक ने इस समझौते को महज कूटनीतिक घोषणा से आगे ले जाने के संकेत दिए हैं। तीनों देशों के विदेश एवं रक्षा नेतृत्व और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई चर्चा से साफ है कि अब इस गठजोड़ की संस्थागत संरचना, सैन्य सहयोग और दीर्घकालिक भूमिका को लेकर गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। इसका असर केवल इन तीन देशों तक सीमित रहने वाला नहीं है, बल्कि आने वाले समय में खाड़ी, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर पर भी पड़ सकता है।

मक्का समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है। इसके तहत किसी एक सदस्य पर होने वाले हमले को व्यापक रूप से साझा सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा जाएगा। ऐसी व्यवस्था किसी पारंपरिक सैन्य गठबंधन की दिशा में पहला कदम हो सकती है, हालांकि इसे अभी औपचारिक रूप से किसी मौजूदा सैन्य संगठन के समकक्ष मानना जल्दबाजी होगी। इसकी वास्तविक ताकत इस बात से तय होगी कि सदस्य देश संकट की स्थिति में एक-दूसरे के लिए किस स्तर तक सैन्य, खुफिया और राजनीतिक सहयोग उपलब्ध कराते हैं।

इस्तांबुल की बैठक ने इस समझौते के व्यावहारिक पक्ष को भी सामने रखा है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय, रक्षा अनुसंधान और हथियारों के उत्पादन में सहयोग जैसे विषय बताते हैं कि गठजोड़ केवल राजनीतिक एकजुटता तक सीमित रखने की योजना नहीं है। यदि तीनों देश रक्षा तकनीक, उत्पादन क्षमता और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाते हैं तो इससे उनकी सामूहिक सामरिक क्षमता में इजाफा हो सकता है। खासतौर पर तुर्किये की तेजी से विकसित होती रक्षा तकनीक, पाकिस्तान का सैन्य अनुभव और सऊदी अरब की आर्थिक क्षमता इस समीकरण को अलग स्वरूप दे सकती है।

इस गठजोड़ की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसका संभावित विस्तार है। यदि भविष्य में दूसरे मुस्लिम बहुल देश इसमें शामिल होते हैं तो इसका भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव काफी बढ़ सकता है। बांग्लादेश की ओर से इसमें शामिल होने को लेकर फिलहाल किसी बड़े जोखिम की संभावना से इनकार किया जाना इस चर्चा को और महत्वपूर्ण बनाता है। वहीं कतर, कुवैत और बहरीन जैसे खाड़ी देशों का नाम भी संभावित विस्तार के संदर्भ में सामने आ रहा है। हालांकि इन देशों के निर्णय केवल धार्मिक या राजनीतिक निकटता पर निर्भर नहीं होंगे। उन्हें अमेरिका, चीन, भारत और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अपने मौजूदा रणनीतिक संबंधों को भी ध्यान में रखना होगा। यही वह बिंदु है जहां इस पूरे घटनाक्रम का भारत के लिए महत्व बढ़ जाता है।

-कांतिलाल मांडोत, सूरत

ललित सुरजन की कलम से

देशबन्धु : चौथा खंभा बनने से इंकार- 8

'छत्तीसगढ़ में शुक्ल बंधुओं के वर्चस्व के कारण अनेक कांग्रेसजन घुटन महसूस करते थे, उन्हें पार्टी में अपने लिए संभावनाएं नजर नहीं आती थी। ऐसे अनेक लोग स्वाभाविक तौर पर सेठीजी के साथ जुड़ गए थे। मैं इनमें से प्रमुख रूप से रायपुर के अमरचंद बैद का नाम लेना चाहूंगा। वे प्रगतिशील विचारों वाले प्रबुद्ध व्यापारी थे और हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। अमरचंद जी अच्छी किताबें खरीदते व पढ़ते थे। उन्होंने निजी लाइब्रेरी बना रखी थी। सेठीजी के कार्यकाल में उनका काफी दबदबा हो गया था। लेकिन अपनी हैसियत का उन्होंने दुरुपयोग किया हो, ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। सेठीजी को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। ऐसा कहा जाता है कि वे नर्वस ब्रेकडाउन के मरीज थे और बीच-बीच में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते थे। इसे लेकर कई किस्से प्रचलित हुए। जितना सच था, उससे ज्यादा उनके विरोधियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो भी निर्णय लिए, उनमें ऐसी कोई बात नहीं दिखी। मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ दिन बाद रायपुर प्रवास के दौरान उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केसी बाजपेयी को खड़े-खड़े सस्पेंड कर दिया था, जिसे लेकर उनकी आलोचना हुई थी। इस तरह के कुछ और अन्य प्रसंग भी रहे होंगे। इन प्रसंगों को एक लंबी पारी में अपवाद ही मानना चाहिए। मुझे उनका एक अलग तरह का प्रसंग याद आता है। शायद खंडवा में लोकसभा उपचुनाव होना था। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के राइस किंग कहे जाने वाले नेमीचंद श्रीश्रीमाल से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की थी। नेमीचंद जी शुक्ल गुट के थे, सो उन्होंने सेठीजी के संदेश की उपेक्षा कर दी। इसके कुछ समय बाद सेठीजी का महासमुंद दौरा हुआ। नेमीचंद जी ने उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया जिसे सेठीजी ने ठुकरा दिया। कुछ देर बाद वे वापसी के लिए हेलीकाप्टर में बैठे और उड़ने के पहले ही अपना टिफिन खोला और भोजन आरंभ कर दिया। हैलीपेड पर उपस्थित लोगों को जो संदेश जाना था, वो चला गया।'

(देशबन्धु में 30 जुलाई 2020 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2020/07/8.html

पावन प्रसंग

जीवन में समायोजन

जीवन में सफलता के माने एकाकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं हैं। जीवन का दायरा बहुत व्यापक है, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक पक्ष भी समाहित हैं, जिनके उचित प्रबंधन के साथ ही व्यक्ति की समग्र सफलता तय होती है। इस संदर्भ में दूरगामी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कौशल है- समायोजन क्षमता, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। समायोजन का अभिप्राय है स्वयं को सामूहिक परिवेश में ढालना, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलना, जिससे उस परिवेश में बिना टकराव के जीवनयापन किया जा सके और अभीष्ट लक्ष्य की ओर निर्बाध रूप से अग्रसर हुआ जा सके। अतः समायोजन लचक, स्वीकृति, सामंजस्य एवं समस्या समाधान की प्रक्रिया है, एक साथ शांति, सौहार्द्र एवं तालमेल के साथ रहने व कार्य करने की क्षमता है।

किसी भी संबंध को लंबे समय तक चलाने के लिए, इसे अनुकूल बनाने की क्षमता का होना आवश्यक होता है। समायोजन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी व साथी-सहचर की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बिठा पाता है, परिस्थितियों के अनुरूप ढलता है और व्यवहार में लचीलापन अपनाते हुए संघर्षपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलता है।

समायोजन में मुख्यतः तीन बातें आती हैं-1. सकारात्मक दृष्टिकोण 2. भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं वाक्-व्यवहार कौशल। इन्हीं के आधार पर आपसी संबंधों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है। यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होगा व साथी-सहचर की कमियों व भिन्नता को सहज रूप से स्वीकार कर पाएगा।

व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो दूसरे पक्ष की भावनाओं को समझते हुए बेहतरीन तालमेल बिठाएगा और व्यवहार कौशल के आधार पर आपसी मतभेदों को सुलझाते हुए वृहद लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा। समायोजन की आवश्यकता परिवार, विद्यालय-महाविद्यालय, कार्यालय या बाहरी किसी अभियान में टीम का हिस्सा बनने पर समायोजन क्षमता ही बड़े प्रोजेक्ट या अभियान की मंजिल तक पहुंचाने में सहायक बनती है। यह आपसी भिन्नता, विचार वैषम्य के बावजूद, बिना अपने मूल्यों से समझौता किए अपने सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति संभव बनाती है।

स्वस्थ रिश्तों को सुनिश्चित करने के लिए समायोजन क्षमता आवश्यक हो जाती है। परस्पर सहानुभूति, लचीलेपन और संवेदी संवाद को अपनाते हुए व्यक्ति आपसी संघर्षों से निपटता है, आत्मविस्तार करता है और रिश्तों को विश्वास एवं सम्मान के आधार पर सुदृढ़ करते हुए चुनौतियों का सृजनात्मक समाधान उपलब्ध करता है।

समायोजन के महत्व से आपसी रिश्ते मधुर व मजबूत बनते हैं। परस्पर सम्मान का भाव विकसित होता है और संबंध लंबे समय तक टिकाऊ बनते हैं।

-अखंड ज्योति

सार-समाचार

कृष्णकुमार राजपूत की स्मृति में 31 पौधे रोपे, संरक्षण का लिया संकल्प

भैरूंदा, देशबन्धु। नर्मदा समग्र हरियाली चुनरी अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडी में स्वर्गीय कृष्णकुमार राजपूत, अतिथि शिक्षक की स्मृति में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नर्मदा तटों पर हरियाली बढ़ाने के साथ पर्यावरण संरक्षण को जनअभियान का स्वरूप देना रहा।

कार्यक्रम में गुरु प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त शिक्षक गुरु दयाल यादव, संस्था प्राचार्य राहुल रावत, राधेश्याम यादव, विजय शर्मा, विद्यालय का समस्त स्टाफ तथा नर्मदा समग्र अभियान से जुड़े उत्तम सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

इस अवसर पर आम, जामुन, चीकू, गुलमोहर, कदम, आंवला और इमली सहित विभिन्न प्रजातियों के 31 पौधे रोपे गए। उपस्थित लोगों ने पौधों के संरक्षण और नियमित देखभाल की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया।

वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। यदि हर व्यक्ति प्रतिवर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखने का संकल्प ले, तो नर्मदा तटों को हराभरा बनाने के साथ जल संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिणाम सामने आएंगे।

उन्होंने युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों से पौधारोपण को जनआंदोलन बनाने तथा 'एक व्यक्ति, एक पौधा' अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। स्वर्गीय कृष्णकुमार राजपूत की स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और उन्हें श्रद्धांजलि देने का प्रेरक प्रयास रहा।

बीमा से वंचित किसानों के लिए भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन

आष्टा, देशबन्धु। भारतीय किसान संघ द्वारा तहसील के विभिन्न बीमा से वंचित किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों की मांग थी कि जिन पात्र किसानों और गांवों को फसल बीमा राशि से वंचित रखा गया है, उन्हें शीघ्र बीमा राशि का लाभ दिलाया जाए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम महेन्द्र किरार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का वाचन तहसील अध्यक्ष द्वारा किया गया। ज्ञापन के बाद अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी के साथ किसानों और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों की विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान किसानों ने बीमा से वंचित गांवों एवं पात्र किसानों की समस्या को प्रमुखता से रखा और शीघ्र बीमा राशि दिलाने की मांग की। अधिकारियों एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि ने किसानों को आश्वासन दिया कि जो किसान पात्र हैं तथा जिन गांवों का बीमा किसी कारणवश छूट गया है, उनके मामले में प्रशासन एवं संबंधित विभाग प्रयासरत हैं। उन्होंने आगामी एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। भारतीय किसान संघ ने स्पष्ट कहा कि फसल बीमा किसान का अधिकार है और पात्र किसानों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि निर्धारित समय में बीमा से वंचित किसानों की समस्या का उचित समाधान नहीं किया गया तथा पात्र किसानों को बीमा राशि नहीं मिली, तो भारतीय किसान संघ आंदोलन को और व्यापक रूप देगा।

जेल में गोलीकांड लापरवाही या मिलीभगत घटना के बाद जेल में सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल

हत्या के आरोपी ने जेल में प्रहरी पर दागी गोली

रायसेन, देशबन्धु। जिला जेल में बुधवार सुबह करीब 9 बजे उस समय हडकंप मच गया, जब हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों का आरोपी नीलेश पटेल कथित तौर पर अवैध कट्टा लेकर जेल से फरार होने की कोशिश करने लगा। आरोपी ने प्रहरी दिग्विजय सिंह को कट्टा दिखाकर गेट की चाबी मांगी और चाबी नहीं देने पर उन्हें गोली मार दी। गोली प्रहरी की कमर के ऊपर लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

घटना ने जिला जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जेल में सामान्य रूप से एक छोटी वस्तु तक की जांच होती है, वहां एक गंभीर अपराध का आरोपी के पास अवैध कट्टा, कारतूस सहित मोबाइल कैसे पहुंचे।

नीलेश पटेल हत्या के एक मामले में आरोपी है। करीब एक वर्ष पहले ग्राम पठारी में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में वह जेल में बंद था। उसके खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। घटनाक्रम की प्रारंभिक जांच के बाद जेल जेल महानिदेशक ने प्रभारी जेल अधीक्षक आरके चौरे को निलंबित कर दिया है।

पहले चाबी मांगी, फिर गोली चला दी : बताया गया कि बुधवार सुबह आरोपी नीलेश पटेल ने लाल गेट और सिल्वर गेट के बीच अचानक कट्टा निकाल लिया और प्रहरी दिग्विजय सिंह को धमकाते हुए फरार होने के लिए गेट की चाबी मांगी। आरोपी काफी देर तक प्रहरी पर चाबी देने का दबाव बनाता रहा। इस दौरान उसने एक-दो चाबियों से ताला खोलने का प्रयास भी किया।

सूत्रों के अनुसार प्रहरी और आरोपी के बीच करीब 10 मिनट तक बहस होती रही। जब प्रहरी ने चाबी देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और आरोपी की फरार होने की कोशिश नाकाम हो गई।

जेल अधीक्षक छुट्टी पर थे, सूचना मिलते ही पहुंचे : जानकारी के अनुसार घटना के समय जेल अधीक्षक आरके चोरे अवकाश पर थे। गोली चलने और प्रहरी के घायल होने की सूचना मिलने पर वे जेल पहुंचे। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी जिला जेल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जेल कर्मचारियों से पूरे मामले की जानकारी ली।

प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था तथा घटना के पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अब जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि हथियार जेल के अंदर किस माध्यम से पहुंचा और सुरक्षा जांच में चूक कहां हुई।

जांच के घेरे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था : घटना ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। गंभीर अपराधों के आरोपियों को रखने वाली जेल में अवैध हथियार का पहुंच जाना अपने आप में बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है।

जेल के भीतर हथियार पहुंचने और प्रहरी पर गोली चलने की यह घटना अब केवल एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि पूरी जेल सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह सुरक्षा में लापरवाही थी, व्यवस्था की चूक या फिर जेल के भीतर किसी संगठित मदद का परिणाम।

बच्चे होते तो क्या होता : जानकारी के अनुसार बुधवार को जेल में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन था। जिसके लिए स्कूली बच्चों को बुलाया गया था। यदि घटना के समय बच्चे स्कूल पहुंच गए होते तो क्या होता। क्या यह एक बड़े हादसे का कारण बनती।

आरोपी के पास मिले प्रतिबंधित सामान : आरोपी नीलेश पटेल के पास के कट्टा नहीं, बल्कि चार कारतूस, एक मोबाइल और गुटखा भी मिला है। यह सभी सामान उस तक कैसे पहुंचे। यह बना मिलीभगत के संभव नहीं लगता है। इसके लिए केवल जेल अधीक्षक नहीं बल्कि अन्य कर्मचारी भी सवालों के घेरे में हैं।

इन बड़े सवालों को चाहिए जवाब : आरोपी नीलेश पटेल तक कट्टा कैसे पहुंचा ?

आरोपी करीब 10 मिनट तक प्रहरी को धमकाता और ताला खोलने का प्रयास करता रहा, तब अन्य सुरक्षा कर्मी कहां थे ?

क्या जेल में बंदियों और मिलने आने वालों की जांच व्यवस्था में कोई गंभीर खामी है ?

इनका कहना है

जेल में गोली चलने के मामले में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी है। फिलहाल जेल अधीक्षक चौरे को निलंबित किया गया है। आगे की कार्रवाई विस्तृत जांच के बाद होगी। जेल विभाग भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है।

मनीष शर्मा, एसडीएम रायसेन

417.96 करोड़ की नाहर परियोजना को राहत

132 केवी लाइन रोकने की कोशिश नाकाम, 2 लाख का लगाया जुर्माना

जबलपुर, देशबन्धु। हाईकोर्ट ने मंडीदीप की 417.96 करोड़ निवेश वाली नाहर परियोजना के लिए प्रस्तावित 132 केवी डीसीएसएस मंडीदीप-नाहर ट्रांसमिशन लाइन को रोकने की कोशिशों को नाकाम करते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं निरस्त कर दीं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने दोनों याचिकाकर्ताओं पर एक-एक लाख रुपये, कुल दो लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि नाहर पाली फिल्म्स लिमिटेड को देने के निर्देश दिए। मामले में दौलत राम इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने ट्रांसमिशन लाइन के वर्तमान मार्ग को चुनौती देते हुए उसे बदलने और निर्माण कार्य रोकने की मांग की थी। नाहर पाली फिल्म्स लिमिटेड की ओर से अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने पक्ष रखा, जबकि एमपीपीटीसीएल की ओर से अधिवक्ता एसपी मिश्र उपस्थित हुए। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग को तकनीकी विशेषज्ञ पहले ही सुरक्षा कारणों से अस्वीकार कर चुके थे। प्रस्तावित मार्ग गैस पाइपलाइन के लिए निर्धारित सुरक्षा दूरी का उल्लंघन करता था। ने कहा कि हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन का मार्ग निर्धारण तकनीकी विशेषज्ञता का विषय है और स्पष्ट मनमानी या कानून के उल्लंघन के अभाव में अदालत विशेषज्ञों के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अधिवक्ता नवतेज सिंह रूपराह ने न्यायालय के समक्ष पूर्व से लंबित सिविल वाद और हाई कोर्ट की कार्यवाही को वर्तमान याचिका में उजागर नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों का हवाला देते हुए उन्होंने इसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का मामला बताया। न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि तथ्य छिपाना विवेकाधीन रिट राहत से वंचित करने का पर्याप्त आधार हो सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि विद्युत अधिनियम के तहत निजी भूमि पर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए भूमि स्वामी की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। परियोजना के 13 में से नौ टावर स्थापित हो चुके हैं। अंततः दोनों याचिकाएं निरस्त कर कुल दो लाख रुपये का जुर्माना नाहर पाली फिल्म्स लिमिटेड के पक्ष में लगाया।

नपाध्यक्ष प्रतिनिधि मेवाड़ा ने माला पहनाकर तीर्थयात्रियों को किया रवाना

आष्टा, देशबन्धु। नगर से जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम की पवित्र तीर्थयात्रा के लिए बुधवार को 52 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान कन्नौद रोड मुकाती बावड़ी के समीप आयोजित एक संक्षिप्त व आत्मीय कार्यक्रम में नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने तीर्थयात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत कर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नपाध्यक्ष प्रतिनिधि रायसिंह मेवाड़ा ने कहा धार्मिक यात्राएं जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति लाती हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य पर सिलवानी नगर परिषद के सीएमओ मिश्रा सम्मानित

सिलवानी, देशबन्धु। नगर परिषद सिलवानी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) राकेश मिश्रा को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (181) में उत्कृष्ट कार्य एवं शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के लिए जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा द्वारा प्रशंसा-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

सोमवार को रायसेन जिले में आयोजित विशेष कार्यक्रम में कलेक्टर ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निराकरण के लिए राकेश मिश्रा की सराहना की। व्यक्तिगत रुचि लेकर शिकायतों का समाधान कराने के परिणामस्वरूप जुलाई 2026 की ग्रेडिंग में नगर परिषद सिलवानी को 96 प्रतिशत वेटेज प्राप्त हुआ। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर रायसेन जिले ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया।

इस अवसर पर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने नगर परिषद के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि भविष्य में भी सभी अधिकारी-कर्मचारी इसी निष्ठा, समर्पण और सेवा भावना के साथ आमजन की समस्याओं का समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण करते रहें।

सम्मान प्राप्त करने के बाद सीएमओ राकेश मिश्रा ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि नगर परिषद सिलवानी की पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय नगर परिषद अध्यक्ष रेशु विभोर नायक, परिषद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देते हुए सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आगे भी नगर परिषद आमजन को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

बलराम बने मालवीय धोबी समाज की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष

सांची, देशबन्धु। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची निवासी एवं नगर परिषद सांची के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा रायसेन के पूर्व जिला महामंत्री तथा वर्तमान पार्षद वार्ड क्रमांक-1 एवं जिला योजना समिति रायसेन के सदस्य बलराम मालवीय को मालवीय धोबी समाज की युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संपूर्ण भारत के धोबी, मालवीय एवं रजक समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने से मध्यप्रदेश के समाजजनों में हर्ष का माहौल है। बताया गया है कि बलराम मालवीय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उससे जुड़े सामाजिक संगठनों की कार्यप्रणाली से जुड़कर अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक कार्यशैली को विकसित किया। लंबे समय से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

सिलवानी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 लाख 50 हजार का ट्रैक्टर किया बरामद

सिलवानी, देशबन्धु। थाना सिलवानी की चौकी जैथारी पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 7.50 लाख रुपये कीमत का आयशर 548 ट्रैक्टर बरामद किया है। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार फरियादी संजू रघुवंशी निवासी ग्राम बीकलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने मई 2026 में आयशर 548 ट्रैक्टर (पंजीयन क्रमांक स्र्क्क38ष्ट1253) 15 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर लिया था। ट्रैक्टर को बीकलपुर वेयरहाउस के पास स्थित मकान के बाहर खड़ा किया गया था, जहां से अज्ञात चोर उसे पीछे लगे कल्टीवेटर सहित चोरी कर ले गए। चोरी गए ट्रैक्टर की कीमत लगभग 7.50 लाख रुपये बताई गई। शिकायत पर थाना सिलवानी में अपराध क्रमांक 265/26, धारा 303(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायसेन आशुतोष गुप्ता के निर्देशन तथा एसडीओपी सिलवानी कुंवर सिंह मुकाती के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत परते के निर्देशन एवं चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुनील सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र एवं लगातार सर्च अभियान के आधार पर कार्रवाई की।

पुलिस ने 1 सितंबर 2026 की रात करीब 1 बजे जंगल क्षेत्र से चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया। इस दौरान ट्रैक्टर चलाकर ले जा रहे दो आरोपियों राहुल अहिरवार (20 वर्ष), निवासी ग्राम रैपुरा एवं राजेन्द्र अहिरवार (18 वर्ष), निवासी ग्राम चुन्हेटिया को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं मामले का तीसरा आरोपी मनोज अहिरवार, निवासी ग्राम रैपुरा अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

इस कार्रवाई में निरीक्षक संजीत परते, उपनिरीक्षक सुनील सिंह भदौरिया, सहायक उपनिरीक्षक परसराम सरलाम, प्रधान आरक्षक प्रेम सिंह राजपूत, आरक्षक विनय कुमार, सोहरत उइके तथा सैनिक शुभम राजपूत की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

शासकीय महाविद्यालय भैरूंदा ने अनुदीप फाउंडेशन से किया समझौता

भैरूंदा, देशबन्धु। विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा और आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालय भैरूंदा के स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ ने अनुदीप फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है।

1 सितंबर को हुए इस समझौते के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों को रोजगारपरक कौशल, करियर मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

महाविद्यालय के अनुसार प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप तैयार करना और उन्हें व्यावहारिक कौशल से सक्षम बनाना है। समझौते के तहत महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित होंगी।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.एस. मीना और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रभारी अक्षय पंवार की उपस्थिति में समझौता संपन्न हुआ। महाविद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस पहल से विद्यार्थियों के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षा और उद्योग जगत के बीच समन्वय स्थापित कर युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने में यह समझौता उपयोगी साबित होगा।

शासकीय आवास की कमी से सरकारी सेवाएं प्रभावित

सांची में दर्जनों विभाग के सैकड़ों कर्मचारी आवास के लिए भटक रहे

सांची, देशबन्धु। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी सांची विकासखंड मुख्यालय होने के साथ प्रशासनिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां जनपद पंचायत, तहसील, नगर परिषद, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पुलिस सहित अनेक शासकीय विभाग संचालित हैं। इन विभागों में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त शासकीय आवास उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते कई कर्मचारी महंगे किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ रोजाना आवागमन कर ड्यूटी करते हैं। दूसरी ओर, कुछ पुराने शासकीय आवासों की स्थिति भी जर्जर बताई जाती है।

जानकारी के अनुसार सांची विकासखंड के अंतर्गत 83 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कामकाज की निगरानी का प्रमुख केंद्र जनपद पंचायत है। यहां अनेक अधिकारी-कर्मचारी पदस्थ हैं, लेकिन शासकीय आवास की सुविधा सीमित होने के कारण अधिकांश कर्मचारियों को स्वयं रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रतिदिन बाहर से आने-जाने वाले कर्मचारियों का काफी समय आवागमन में खर्च होता है। इससे आपातकालीन अथवा अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों के समय तत्काल उपलब्धता भी चुनौती बन सकती है।

नगर परिषद के कर्मचारियों को भी आवास नहीं : *नगर परिषद सांची में सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले करीब 65 स्थायी और अस्थायी अधिकारी-कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। इनके लिए भी पर्याप्त शासकीय आवास उपलब्ध नहीं हैं। कई कर्मचारी किराए के मकानों में रहते हैं, जबकि कुछ प्रतिदिन आवागमन करते हैं। विडंबना यह है कि नगर परिषद का नया भवन तैयार हो गया, लेकिन वहां सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। बताया जाता है कि पूर्व में नगर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए आवास और विश्राम गृह जैसी व्यवस्थाएं थीं, लेकिन इनके समाप्त होने के बाद वैकल्पिक आवास की जरूरत पूरी नहीं हुई।*

पुलिसकर्मी भी किराए के मकानों में रहने को मजबूर : *सांची में देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ विशिष्ट और अतिविशिष्ट लोगों का लगातार आवागमन होता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी रहती है। पर्याप्त सरकारी आवास नहीं होने के कारण अनेक पुलिसकर्मी किराए के मकानों में रहने को विवश हैं। कुछ पुराने भवनों की स्थिति को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।*

अस्पताल और विद्यालय में भी यही स्थिति : *शासकीय सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीब 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और 30 से अधिक शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। यहां भी शिक्षकों और प्राचार्य के लिए पर्याप्त आवासीय सुविधा नहीं है। इसी तरह सिविल अस्पताल में चिकित्सकों सहित करीब 60 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं हैं। करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल का नया भवन तैयार हो गया, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों के आवास की जरूरत पूरी नहीं हुई।*

तहसील कार्यालय, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कन्या छात्रावास और महिला एवं बाल विकास विभाग में भी आवासीय समस्या बनी हुई है। महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय लंबे समय से किराए के भवन में संचालित होने की बात सामने आती रही है। विभाग से जुड़े कुछ शासकीय भवनों पर अतिक्रमण की स्थिति भी बताई जाती है।

सांची में लगातार नए शासकीय भवनों के निर्माण पर राशि खर्च की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा अब भी पर्याप्त नहीं है। स्थानीय स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप शासकीय आवासों का निर्माण, पुराने आवासों का पुनर्निर्माण और अतिक्रमण वाले भवनों को मुक्त कराकर उपयोग में लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सरकारी सेवाओं की निरंतरता और कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए आवास की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है।

सार समाचार

हरछठ पर महिलाओं ने किया पूजन-अर्चन, संतान की दीर्घायु की कामना

गंजबासौदा, देशबन्धु। हरछठ का पर्व बुधवार को नगर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया तथा भगवान बलराम और हरछठ माता की पूजा कर अपनी संतान की सुख-समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना की। पूजन के लिए महिलाओं ने घरों में हरछठ माता की वेदी सजाई। पूजा स्थल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित कर कथा का श्रवण किया गया। महिलाओं ने एक-दूसरे को हरछठ पर्व की शुभकामनाएं दीं। कई स्थानों पर सामूहिक रूप से महिलाओं ने एकत्रित होकर पूजन-अर्चन किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार हरछठ का व्रत माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं। पर्व के दौरान महिलाओं ने परंपरागत रीति-रिवाजों के साथ पूजा संपन्न की। पूरे दिन नगर में धार्मिक वातावरण बना रहा।

लगातार चोरी की वारदातों से बढ़ी चिंता, 10 दिन में एक ही घर में दूसरी बार चोरी

सिरोंज, देशबन्धु। नगर में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक नागरिक गौरव सोनी की पोस्ट के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

गौरव सोनी ने अपनी पोस्ट में बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर में चोरी हुई थी, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद अब करीब 10 दिन के भीतर उनके घर में दोबारा चोरी की घटना हो गई। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से क्षेत्र बड़ा होने और कर्मचारियों की कमी की बात कही जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं के पीछे नशेड़ियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चोरी की घटनाओं पर इसी तरह कारण गिनाकर कार्रवाई होती रहेगी तो आम जनता और गरीब परिवारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव त्यागी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की सलाह देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने पर चोरी के मामलों में जल्द कार्रवाई हो सकती है। बसंती लाल कुशवाहा ने भी सिरोंज में घरों के साथ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रशासन से विशेष ध्यान देने की मांग की।

वहीं अशोक कुशवाहा ने चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई, जबकि रवि राज सिरोंज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गौरव सोनी के घर में हुई चोरी काफी गंभीर थी और चोर घर की पीछे की दीवार तक तोड़कर सामान ले गए। हर्षवर्धन नामदेव ने भी चोरी के मामलों में शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर नागरिकों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का भी शीघ्र खुलासा करना चाहिए।

जिला जेल सहित उप जेलों में प्रशासन-पुलिस का संयुक्त निरीक्षण

बैरकों की नशीले पदार्थ की हुई जांच, हथियार, मोबाइल अथवा प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली

▶ **सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा**

विदिशा, देशबन्धु। जिला कलेक्टर अंशुल गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका तिवारी के मार्गदर्शन तथा एसडीएम विदिशा मनीष जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह की उपस्थिति में जिला जेल विदिशा में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण एवं सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इसी क्रम में उप जेल गंजबासौदा एवं उप जेल लटेरी में भी संयुक्त औचक निरीक्षण एवं सघन तलाशी की कार्रवाई की गई।

निरीक्षण के दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों, साफ-सफाई, भोजन व्यवस्था, बंदियों के रिकॉर्ड, प्रवेश-निकास व्यवस्था एवं सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

इस दौरान बंदियों के बैरकों में रखे सामान एवं बिस्तरों की रैंडम चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान किसी भी बंदी के पास नशीले पदार्थ, धूम्रपान सामग्री, अवैध कट्टा/चाकू, मोबाइल फोन अथवा अन्य कोई अवांछनीय एवं प्रतिबंधित वस्तु नहीं पाई गई।

जेल के मुख्य प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के प्रवेश एवं निकासी संबंधी रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों की भी जांच की गई। साथ ही बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों एवं अन्य आगंतुकों से संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

सघन जांच के दौरान किसी भी प्रकार के हथियार, मादक पदार्थ, धूम्रपान सामग्री, मोबाइल फोन अथवा अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुए। इस दौरान जिला जेल विदिशा के समस्त बैरकों, पाकशाला, जेल परिसर के बाहरी क्षेत्रों एवं अन्य स्थानों की सघन जांच की गई। इस कार्रवाई में रक्षित निरीक्षक नीरज सिकरवार, कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक हिरदय कुशराम, थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक राजपाल सिंह जादौन एवं उप निरीक्षक वी.डी. सिंह सहित पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी एवं निरीक्षण किया गया।

उप जेल लटेरी एवं उप जेल गंजबासौदा में भी प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया। उप जेल लटेरी में डिप्टी जेलर रवि मरावी एवं एसडीएम लटेरी अनिल कछवारे तथा थाना प्रभारी लेटर निरीक्षक वीमेंदु व्यंकट टांडिया की उपस्थिति में जेल की सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। दोनों उप जेलों में भी बैरकों एवं परिसर की सघन जांच कर आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

स्थाई वारंटी तामील अभियान, एक माह में 284 स्थाई वारंट तामील

विदिशा, देशबन्धु। जिले में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों एवं स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी के निर्देशन में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष स्थाई वारंटी तामील अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लंबे समय से फरार चल रहे स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अनुभाग स्तर पर दो-दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों को स्थाई वारंटियों की जानकारी एकत्रित करने, उनके संभावित ठिकानों की तलाश करने तथा सूचना तंत्र को सक्रिय कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई।

अभियान के तहत पुलिस टीमों द्वारा लगातार मुखबिर तंत्र, तकनीकी संसाधनों एवं उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी के आधार पर स्थाई वारंटियों की तलाश की गई। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने समन्वित रूप से कार्रवाई करते हुए एक माह में कुल 284 स्थाई वारंट तामील कर फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में ऐसे स्थाई वारंटी भी शामिल रहे, जो 7, 10, 12, 15 एवं 18 वर्षों से फरार चल रहे थे। लंबे समय से न्यायालयीन प्रक्रिया से बच रहे इन आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। सभी आरोपियों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी, समस्त एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों द्वारा लगातार अभियान की मॉनिटरिंग की गई। थाना स्तर पर गठित विशेष टीमों द्वारा स्थाई वारंटियों की सूची का विश्लेषण कर उनकी वर्तमान स्थिति, संभावित ठिकानों एवं संपर्क सूत्रों की जानकारी जुटाई गई तथा टीमों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपकर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए।

पुलिस टीमों द्वारा जिले के साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाकर आवश्यकतानुसार दबिश दी गई। इस दौरान लंबे समय से फरार चल रहे कई स्थाई वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

एक माह तक चले विशेष अभियान में 284 स्थाई वारंटों की तामील कर विदिशा पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की।

दिनभर रिमझिम बारिश से मौसम हुआ सुहाना

▶ **गर्मी और उमस से मिली राहत**

गंजबासौदा, देशबन्धु। शहर में बुधवार को दिनभर मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और रुक-रुककर रिमझिम बारिश का दौर चलता रहा। कभी हल्की बूंदाबांदी तो कभी कुछ देर तेज बौछारों ने मौसम को सुहाना बना दिया। लगातार बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।

सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू होने के कारण शहर की सडक़ों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित रही। दोपहिया वाहन चालकों को बारिश के बीच आवागमन करना पड़ा, वहीं कई लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। बाजार में भी बारिश का असर दिखाई दिया और सामान्य दिनों की अपेक्षा चहल-पहल कम रही।

दिनभर रिमझिम बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। बारिश थमने के बाद कुछ समय के लिए बादल छंटे, लेकिन फिर आसमान में बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम में लगातार बदलाव के चलते लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की।

बाक्स-किसानों के लिए बारिश राहत लेकर आई

बारिश को खरीफ फसलों के लिए भी उपयोगी माना जा रहा है। खेतों में खड़ी फसलों को पानी मिलने से किसानों को राहत मिली है। हालांकि लगातार बारिश होने पर निचले खेतों में पानी भरने की स्थिति बनने की आशंका भी बनी हुई है। किसानों की नजर अब आने वाले दिनों के मौसम पर टिकी हुई है। शहर के कुछ निचले हिस्सों में बारिश का पानी सडक़ों पर जमा होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। लंबे समय तक रिमझिम बारिश के बावजूद फिलहाल कहीं बड़े जलभराव की स्थिति सामने नहीं आई। मौसम में बदलाव के चलते आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।

बलराम जयंती एवं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की जयंती मनाई

गंजबासौदा, देशबन्धु। शहर वाचनालय पाठक संघ के तत्वाधान में बुधवार को भगवान बलराम जयंती एवं प्रसिद्ध संत स्वामी स्वरूपानंद जी शंकराचार्य की जयंती गरिमामय एवं सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। इस अवसर पर उज्जैन निवासी स्वर्गीय श्रीकृष्ण सरल की पुण्यतिथि भी मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन पाठक संघ के संयोजक दीपक तिवारी ने किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय नारायण सदाशिव पिंगले सेवा संस्थान के सुनील बाबू पिंगले ने स्वामी स्वरूपानंद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके सिद्धांतों और आचरण से प्रेरणा लेकर जीवन में उन्हें अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणादायी बताया।इस अवसर पर पंडित देवेंद्र दुबे, उत्तम सोनी, वाचनालय प्रभारी कुलदीप राजपूत एवं मोहन सैनी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

हेमंत को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा में रायसेन जिले की जिम्मेदारी

विदिशा/सिरोंज, देशबन्धु। विदिशा के युवा समाजसेवी एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हेमंत विश्वकर्मा को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने रायसेन जिले का प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की खबर से विदिशा सहित प्रदेशभर के विश्वकर्मा समाज में हर्ष और उत्साह का माहौल है।

सिरोंज निवासी बबलू विश्वकर्मा ने हेमंत विश्वकर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि हेमंत विश्वकर्मा सर्व विश्वकर्मा समाज समिति के पूर्व युवा प्रदेश अध्यक्ष एवं विश्वकर्मा महापंचायत के पूर्व युवा प्रदेश महामंत्री के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सामाजिक एवं संगठनात्मक क्षेत्र में उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।

उनकी नियुक्ति पर प्रदेशभर से समाजजनों, युवा साथियों और शुभचिंतकों द्वारा हेमंत विश्वकर्मा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। समाजजनों ने विश्वास जताया कि वे नई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

लगातार चोरी की वारदातों से बढ़ी चिंता, 10 दिन में एक ही घर में दूसरी बार चोरी

सिरोंज, देशबन्धु। नगर में लगातार सामने आ रही चोरी की घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक नागरिक गौरव सोनी की पोस्ट के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन से चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

गौरव सोनी ने अपनी पोस्ट में बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर में चोरी हुई थी, जिसकी प्राथमिकी उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद अब करीब 10 दिन के भीतर उनके घर में दोबारा चोरी की घटना हो गई। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से क्षेत्र बड़ा होने और कर्मचारियों की कमी की बात कही जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा ऐसी घटनाओं के पीछे नशेड़ियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि चोरी की घटनाओं पर इसी तरह कारण गिनाकर कार्रवाई होती रहेगी तो आम जनता और गरीब परिवारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव त्यागी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने की सलाह देते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों तक शिकायत पहुंचने पर चोरी के मामलों में जल्द कार्रवाई हो सकती है। बसंती लाल कुशवाहा ने भी सिरोंज में घरों के साथ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रशासन से विशेष ध्यान देने की मांग की।

वहीं अशोक कुशवाहा ने चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई, जबकि रवि राज सिरोंज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गौरव सोनी के घर में हुई चोरी काफी गंभीर थी और चोर घर की पीछे की दीवार तक तोड़कर सामान ले गए। हर्षवर्धन नामदेव ने भी चोरी के मामलों में शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की।

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर नागरिकों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को रात्रि गश्त बढ़ाने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का भी शीघ्र खुलासा करना चाहिए। हालांकि, चोरी की घटनाओं के पीछे नशेड़ियों के शामिल होने संबंधी पुलिस की बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

आग से बचाव के लिए व्यापारिक संस्थानों, अस्पतालों व विद्यालयों को दिया प्रशिक्षण

सिरोंज, देशबन्धु। नगरपालिका परिषद सिरोंज के कार्यालय में बुधवार को व्यापारिक संस्थानों, निजी अस्पतालों, विद्यालयों एवं होटल संचालकों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण विदिशा से आए होमगार्ड एवं राज्य आपदा आपातकालीन बल के जिला कमांडर मयंक जैन के नेतृत्व में दल द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान संस्थान संचालकों को आगजनी की घटनाओं से बचाव और आग लगने की स्थिति में अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि सभी व्यापारिक संस्थानों, निजी अस्पतालों, विद्यालयों, होटलों सहित अन्य संबंधित प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा उपकरण रखना आवश्यक है। साथ ही संबंधित संस्थानों के लिए नगरपालिका से अग्नि अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना भी अनिवार्य बताया गया।

प्रशिक्षण में आग के विभिन्न प्रकारों और उन्हें बुझाने के तरीकों की जानकारी दी गई। लकड़ी, कोयला, कागज और कपड़े जैसी वस्तुओं से लगने वाली आग को पानी से बुझाया जा सकता है। पेट्रोल, तारकोल आदि से लगने वाली आग में ऑक्सीजन का संपर्क रोककर आग पर काबू पाने की जानकारी दी गई। एलपीजी गैस से लगी आग के लिए गैस अथवा पाउडर आधारित अग्निशमन यंत्र के उपयोग के बारे में बताया गया। धातु जैसे ठोस पदार्थों में लगने वाली आग के लिए संबंधित रासायनिक प्रक्रिया के अनुसार अग्निशमन तथा विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट अथवा अन्य कारणों से लगी आग में पहले विद्युत आपूर्ति बंद करने की जानकारी दी गई।दल द्वारा आग बुझाने में उपयोग होने वाले सामान्य उपकरणों, जैसे स्ट्रिप पंप, अग्निशमन यंत्र, लोहे की बाल्टी, रेत, सोडा-एसिड, झाग एवं निष्क्रिय गैस आदि के उपयोग की जानकारी भी दी गई।

सिरोंज-बीना फोरलेन की घोषणा पर उठे सवाल, कांग्रेस ने पूछा

स्वीकृत मार्ग में सिरोंज को क्यों नहीं किया शामिल

सिरोंज, देशबन्धु। सिरोंज क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। मेहलुआ चौराहा से बीना-मालथौन तक सड़क निर्माण की स्वीकृति को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र रघुवंशी ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि 17 जनवरी 2026 को विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में सिरोंज-बीना चार लेन सड़क की घोषणा की गई थी, लेकिन अब स्वीकृत मार्ग में सिरोंज का नाम दिखाई नहीं दे रहा है।

रघुवंशी ने कहा कि जनवरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में सिरोंजङ्कबीना चार लेन सड़क को लेकर घोषणा की गई थी। घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद जगी थी कि सिरोंज को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उनका कहना है कि वर्तमान स्वीकृति में सिरोंज को शामिल नहीं किए जाने से लोगों के बीच यह सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है कि आखिर पूर्व में की गई घोषणा का क्या हुआ।

उन्होंने कहा कि सागर संसदीय क्षेत्र में भाजपा का सांसद, सिरोंज का विधायक तथा प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। ऐसे में यदि सिरोंज को इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का लाभ नहीं मिलता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

रघुवंशी ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के व्यापार, कृषि और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण होता है। सिरोंज और आसपास के हजारों किसान अपनी कृषि उपज को बड़ी मंडियों और व्यापारिक केंद्रों तक पहुंचाते हैं। बेहतर सड़क सुविधा मिलने से किसानों के परिवहन समय और खर्च में कमी आ सकती है तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।उन्होंने कहा कि सिरोंज-लटेरी क्षेत्र लंबे समय से रेलवे सुविधा की मांग करता आ रहा है। क्षेत्र में बड़े उद्योगों का भी अभाव है। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण युवाओं को दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है। ऐसे में सड़क संपर्क से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं में सिरोंज को शामिल किया जाना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मांग की कि सिरोंज-मेहलुआ चौराहा-कुरवाई-बीना-मालथौन को जोड़ने वाले मार्ग पर विचार करते हुए सिरोंज को प्रस्तावित सड़क परियोजना में शामिल किया जाए। रघुवंशी ने कहा कि सिरोंज की जनता लंबे समय से सड़क, रेलवे, उद्योग और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग करती रही है। सरकार को इन मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उस घोषणा की वर्तमान स्थिति क्या है। सिरोंज को बेहतर सड़क संपर्क मिलना क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है।

परिणाम के बाद विज्ञापित पदों में बदलाव संभव नहीं, जुलाई 2027 तक रिक्तियों की गणना जारी

शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थिति की स्पष्ट

भोपाल, देशबन्धु। शिक्षक भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाने की मांग के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद किसी भर्ती में विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। नए रिक्त पदों को अगली भर्ती में शामिल किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने से रिक्त रह गए बैकलॉग पदों को अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं भरा जा सकता।

विभाग के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में 7591 पद विज्ञापित किए गए थे। कर्मचारी चयन मंडल से 3650 अभ्यर्थियों की चयन सूची मिली, जिनमें से 3194 के नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। 456 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से जुड़ी प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणों के कारण लंबित है। पूरक चयन परीक्षा और आयु सीमा में छूट से जुड़े मामले सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। इन मामलों में अगली सुनवाई 25 सितंबर 2026 को निर्धारित है।

माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2025-26 में 7082 पद विज्ञापित हुए, जिनमें 6468 पद भर्ती के लिए उपलब्ध रहे। 4005 अभ्यर्थियों की चयन सूची प्राप्त हुई और 3699 के नियुक्ति आदेश जारी किए गए। शेष पदों पर पात्रता के अनुसार प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 10150 पद विज्ञापित किए गए, जिनमें 9161 भर्ती के लिए उपलब्ध रहे। 7962 अभ्यर्थियों की चयन सूची मिली और 6922 के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। शेष पदों पर दस्तावेज और दिव्यांग अभ्यर्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। विभाग ने बताया कि वर्तमान में कुल 72901 पद रिक्त हैं। इनमें 59073 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। पदोन्नति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को ही पदोन्नति देने का अभिमत प्राप्त हुआ है।

विभाग आगामी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहा है। जुलाई 2027 तक रिक्तियों की गणना की जा रही है। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल 18088 रिक्त पदों में 8038 बैकलॉग, 10050 नए और 3990 अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 प्रतिशत आरक्षण के कारण रोककर रखे गए पद हैं। विभाग ने संकेत दिया है कि रिक्तियों का आकलन पूरा होने के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।

सीनियर सिटिजन पुलिस पंचायत में 4 प्रकरणों की सुनवाई

बुजुर्ग को पोतों से मिली राहत, पुत्र द्वारा भूमि गिरवी का मामला कोतवाली भेजा

__विदिशा, देशबन्धु।__ पुलिस अधीक्षक विदिशा रोहित काशवानी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित सीनियर सिटिजन पुलिस पंचायत की बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कुल 4 प्रकरणों की सुनवाई की गई। बैठक में कोर कमेटी के सदस्य डॉ. सचिन गर्ग उपस्थित रहे।

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े पारिवारिक एवं संपत्ति संबंधी विवादों को संवेदनशीलता एवं आपसी संवाद के माध्यम से सुना गया। वर्षों से लंबित मामलों में दोनों पक्षों की बात समझते हुए आपसी सहमति एवं समझाइश के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया गया।

विदिशा निवासी एक वरिष्ठ महिला द्वारा शिकायत की गई कि उनके स्वर्गीय पुत्र के दोनों बेटे उनके साथ गाली-गलौज करते हैं तथा उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं। पंचायत कोर कमेटी द्वारा दोनों पक्षों की बात संवेदनशीलता एवं धैर्यपूर्वक सुनी गई। संवाद एवं समझाइश के माध्यम से मामले का समाधान कराया गया। विदिशा निवासी एक बुजुर्ग द्वारा शिकायत की गई कि उनका पुत्र उनकी भूमि को अन्य व्यक्तियों के पास गिरवी रखकर राशि प्राप्त कर रहा है।

पंचायत में दोनों पक्षों को सुनकर मामले की वास्तविक स्थिति को समझा गया। आवेदक द्वारा पुत्र द्वारा लगातार परेशान किए जाने की बात भी बताई गई। पंचायत द्वारा धैर्यपूर्वक सुनवाई के उपरांत प्रकरण को उचित वैधानिक कार्रवाई हेतु थाना कोतवाली भेजा गया।

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित अन्य प्रकरणों की भी सुनवाई की गई। कुछ मामलों में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा कुछ प्रकरणों में संबंधित पक्षों एवं साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आगामी तिथियां निर्धारित की गईं।

[अर्थ जगत]

सर्वाधिक बढ़ने वाले शेयर

अडानी पोर्ट्स	1.63 प्रतिशत
बजाज फिनसर्व	1.02 प्रतिशत
पावरग्रिड	1.00 प्रतिशत
एनटीपीसी	0.96 प्रतिशत
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1.74 प्रतिशत

सर्वाधिक घटने वाले शेयर

एशियन पेंट्स	1.61 प्रतिशत
एचडीएफसी बैंक	1.56 प्रतिशत
महिंद्रा एंड महिंद्रा	1.56 प्रतिशत
एचसीएल टेक्नो	1.49 प्रतिशत
बीईएल	1.33 प्रतिशत

सर्राफा

सोना (प्रति दस ग्राम)स्टैंडर्ड	1,54,940
बिटुर	88,730
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	39,795
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	2,36,000
वायदा	70,857
चांदी सिक्का लिवाली	900
बिकवाली	880

मुद्रा विनिमय

मुद्रा	क्रय	विक्रय
अमेरिकी डॉलर	96.39	93.32
पौंड स्टर्लिंग	131.03	126.39
यूरो	112.26	108.08
चीन युआन	15.06	13.34

अनाज

देसी गेहूँ एमपी	2400-3000
गेहूं दड़ा	2862.70
आटा	2800-2900
मैदा	2900-2950
चोकर	2000-2100

मोटा आनाज

बाजरा	1300-1305
मक्का	1350-1500
ज्वार	3100-3200
जौ	1430-1440
काबुली चना	3500-4000

शुगर

चीनी एस	5,803
चीनी एम	4500-4600
मिल डिलीवरी	3620-3720
गुड़	5,976

दाल-दलहन

चना	5700-5800
दाल चना	7975.80
मसूर काली	8217.40
उड़द दाल	11320.41
मूंग दाल	10205.58
अरहर दाल	11451.54

जियोपीसी का सबस्क्रिप्शन अब सबके लिए उपलब्ध

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। रिलायंस जियो ने अपने जियोपीसी को दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर तथा ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर के कनेक्शन वाले ग्राहकों के लिए भी खोल दिया है। कंपनी ने बुधवार को बताया कि जियोपीसी अब इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अलग सब्सक्रिप्शन के तौर पर उपलब्ध है। पहले यह सिर्फ़ जियोहोम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध था। अब किसी भी मौजूदा कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर जियोपीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है।

विश्व बैंक के साथ अब टूरिज्म व डिजिटल हब पर भी साथ काम करेगा भारत

एशविले, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। भारत और विश्व बैंक ग्रुप ने अपनी साझेदारी को पारंपरिक कर्ज देने से आगे ले जाने पर चर्चा की। अब दोनों का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और प्राइवेट कैपिटल जुटाने पर ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान एशविले में विश्व बैंक ग्रुप के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई।

बयान के मुताबिक, वित्त मंत्री सीतारमण ने भारत के साथ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लगातार जुड़ाव का स्वागत किया। उन्होंने 1.5 अरब डॉलर के डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग को तेजी से प्रोसेस करने के लिए आभार जताया।

वित्त मंत्री ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) के उस सहयोग का भी स्वागत किया, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (एसआईडीबीआई) के जरिए एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है। बयान में कहा गया कि यह मदद रिकॉर्ड समय में प्रोसेस की गई

■ भारत-वर्ल्ड बैंक ग्रुप पार्टनरशिप को मजबूत करने व फाइनेंसिंग टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल पर हुई चर्चा

और इसका भारत के एमएसएमई सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ा है। बैठक में भारत-वर्ल्ड बैंक ग्रुप पार्टनरशिप को मजबूत करने और फाइनेंसिंग टूल्स के ज्यादा इस्तेमाल पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) की बड़ी भूमिका पर बात की। इस प्रस्तावित सहयोग के तहत गारंटी के व्यवस्थित इस्तेमाल और ज्यादा प्राइवेट पूंजी जुटाकर देश के कॉर्पोरेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेक्टर-बेस्ड, प्रोग्रामेटिक अप्रोच पर भी विचार किया। इस तरह की व्यवस्था से साझेदारी का फोकस अलग-अलग प्रोजेक्ट से हटकर बड़े सेक्टर्स के प्रोग्राम पर होगा। अजय बंगा ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बड़े बदलाव का जिक्र किया।

भारत सड़क व डिजिटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में कर रहा बेहतर कार्य : अजय बंगा

एशविले। भारत सड़क, एयरपोर्ट और डिजिटाइजेशन जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य कर रहा है और देश में अर्थव्यवस्था की विकास दर को मौजूदा 7-8 प्रतिशत के पार जाने की क्षमता मौजूद है। यह बयान विश्व बैंक प्रमुख अजय बंगा ने दिया। बंगा का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब भारत ने वैश्विक अस्थिरता के बीच वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की है। श्री बंगा ने कहा कि वृद्धि दर के ताजा आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब लगातार 7 से 8 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर रहा है, जो काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि इससे भी आगे जाने का मौका है। उन्होंने कहा कि उस 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर में सर्विस सेक्टर और निर्यात दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। निवेश का स्तर भी बना हुआ है। इस कारण मुझे लगता है कि भारत ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है। वर्ल्ड बैंक के प्रमुख ने कहा कि ध्यान सिर्फ एक तिमाही से आगे बढ़कर, इस बढ़ोतरी को युवाओं के लिए रोजगार और मौकों में बदलने पर होना चाहिए।

विकास दर को 8 प्रतिशत के पार ले जाने की क्षमता मौजूद

एसजीएसटी संग्रह में हरियाणा ने देशभर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की

चंडीगढ, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह में हरियाणा ने देशभर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में प्रदेश का एसजीएसटी संग्रह 29 प्रतिशत बढ़कर 24,662 करोड़ पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 16 प्रतिशत रही। हरियाणा डीपीआर की ओर से यह जानकारी दी गई है।

डीपीआर के मुताबिक, अगस्त 2026 में भी एसजीएसटी से 4,982 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। देश के कुल जीएसटी करदाताओं में 4 प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी के बावजूद हरियाणा का कुल जीएसटी संग्रह में योगदान लगभग 7.7 प्रतिशत है।

2 अगस्त को एक्स पोस्ट में डीपीआआर ने कहा था, 'हरियाणा ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में

■ राष्ट्रीय औसत 13 प्रतिशत के मुकाबले 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह वृद्धि के मामले में देशभर में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत 13 प्रतिशत के मुकाबले 28 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। वहीं, जुलाई 2026 में हरियाणा का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 5,135 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2026-27 के पहले चार महीनों में प्रदेश का पोस्ट-सेटलमेंट एसजीएसटी संग्रह 19,680 करोड़ रुपए दर्ज किया गया।

भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 2029 तक 6 गीगावाट होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। भारत का डेटा सेंटर इंडस्ट्री की क्षमता जून 2026 तक 1.6 गीगावाट की क्षमता से बढ़कर 2029 तक 6 गीगावाट होने की उम्मीद है। इसके लिए करीब 110 अरब डॉलर की पूंजी की जरूरत होगी। इस वृद्धि को एआई वर्कलोड और हाइपरस्केल क्लाउड की तैनाती से बढ़ावा मिलेगा। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।

जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में डेटा सेंटर क्षेत्र में 101 मेगावाट की मांग दर्ज की गई, जो पिछले तीन वर्षों के पहली छमाही के औसत से 20 प्रतिशत से अधिक है।

इस अवधि में आपूर्ति भी मजबूत रही और 85 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जो मुख्य रूप से मुंबई और चेन्नई में केंद्रित रही। पहले से बुक की गई क्षमता की तेजी से डिलीवरी के कारण डेटा सेंटर में मौजूद खाली क्षमता घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गई, जो बाजार की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक हाइपरस्केलर कंपनियां बाजार की गतिशीलता को मूल रूप से बदल रही हैं। वे नई क्षमता का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सेल्फ-बिल्ड सुविधाओं के जरिए विकसित करने की प्रतिबद्धता जता रही हैं। हाइपरस्केल सेल्फ-बिल्ड परियोजनाओं के तहत 2029 तक 1.4 गीगावाट क्षमता उपलब्ध होने की उम्मीद है। बड़े निवेश के चलते हैदराबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहर गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर हब में बदल रहे हैं।

भारत के ई-मोबिलिटी परिवर्तन को सिर्फ ईवी बिक्री से न आंके : कुमारस्वामी

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट उद्योग से प्रौद्योगिकी, डिजाइन और घरेलू मूल्यवर्धन में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिवर्तन का आकलन केवल बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए।

यहां ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) के 66 वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत के गतिशीलता परिवर्तन के अगले

■ तकनीक व लोकल वैल्यू पर ध्यान देने की जरूरत

चरण में पैमाने का निर्माण, स्थानीयकरण को गहरा करने, नवाचार में तेजी लाने और देश को उन्नत और हरित गतिशीलता प्रौद्योगिकियों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

एचडी कुमारस्वामी ने कहा, 'हमारी सफलता को केवल बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। इसे इस बात से भी मापा जाना चाहिए कि भारत में कितनी तकनीक विकसित की गई है, घरेलू स्तर पर कितना मूल्यवर्धन किया गया है, नई आपूर्ति श्रृंखलाओं में कितने लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भाग ले रहे हैं और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजारों में कितनी प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 'उन्होंने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं से स्वच्छ, अधिक कुशल और उभरती प्रौद्योगिकियों में अधिक साहसपूर्वक निवेश करने का आह्वान किया।

बिकवाली के दबाव से बाजार में गिरावट जारी

मुंबई, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। विदेशों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को बिकवाली हावी रही और प्रमुख सूचकांक करीब छह सप्ताह के निचले स्तर पर बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 473 अंक टूटकर 76,471.32 अंक पर खुला और कुछ ही देर में 800 अंक से ज्यादा लुढ़कते हुए 76,136 अंक तक उतर गया। कारोबार की समाप्ति पर यह 373.83 अंक (0.49 प्रतिशत) नीचे 76,570.35 अंक पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-50 सूचकांक भी 141.35 अंक यानी 0.59 प्रतिशत नीचे 23,914.45 अंक पर बंद हुआ। दोनों प्रमुख सूचकांकों का यह 24 जुलाई के बाद का निचला स्तर है।

दुनिया के लगभग सभी प्रमुख शेयर बाजारों में बिकवाली देखी गई। भारतीय शेयर बाजारों पर भी इसका असर हुआ और निवेश धारणा कमजोर हुई। एशिया में आज जापान का निक्केई करीब तीन प्रतिशत नीचे बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार भी लाल निशान में हैं। अमेरिकी शेयर बाजारों में भी मंगलवार को गिरावट रही थी।

घरेलू स्तर पर तेल एवं गैस, रियल्टी और सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी समूहों

■ सेंसेक्स 0.49 प्रतिशत नीचे 76,570.35 अंक पर रहा
■ निफ्टी 0.59 प्रतिशत नीचे 23,914.45 अंक पर बंद

में बिकवाली हावी रही। ऑटो और मीडिया समूहों के सूचकांक पौने दो प्रतिशत गिर गए। आईटी में 1.25 फीसदी की गिरावट रही। बैंकिंग, वित्त, एफएमसीजी, धातु, स्वास्थ्य और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों के सूचकांक भी टूट गए। वृहत बाजार में भी निवेशकों का विश्वास कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.70 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.37 प्रतिशत फिसल गया।

एनएसई में जिन 3,630 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ उनमें से 2,072 के शेयर लाल निशान में और 1,445 के हरे निशान में रहे। अन्य 113 कंपनियों के शेयर अंतत: अपरिवर्तित बंद हुए।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 20 के शेयरों में गिरावट रही। एशियन पेंट्स ने सबसे अधिक 1.61 प्रतिशत का नुकसान उठाया। एचडीएफसी बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.56 फीसदी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1.49, बीईएल का 1.33, इंफोसिस का 1.28, भारतीय स्टेट बैंक का 1.22, इंडिगो 1.00 और हिंदुस्तान यूनीलिवर का 0.95 प्रतिशत टूट गया। टीसीएस, टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक और इटरनल के शेयर भी उतर गये।

अडानी पोर्ट्स में 1.63 प्रतिशत की तेजी रही। बजाज फिनसर्व का शेयर 1.02 प्रतिशत, पावरग्रिड का 1.00 प्रतिशत और एनटीपीसी का 0.96 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ। टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेंट और बजाज फाइनेंस के शेयर भी हरे निशान में रहे।

वैश्विक स्तर पर एशिया में जापान का निक्केई 2.85 प्रतिशत, चीन का शंघाई कंपोजिट 0.97 प्रतिशत और 0.07 प्रतिशत टूट गया। यूरोपीय बाजारों में शुरुआती कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.43 प्रतिशत और ब्रिटेन का एफटीएसई 0.32 प्रतिशत नीचे था।

जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाकर 'ए- स्टेबल' किया

मुंबई, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी है। जापान क्रेडिट रेटिंग (जेसीआर) एजेंसी ने भारत की 'फॉरेन करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग' और 'लोकल करेंसी लॉन्ग-टर्म इश्यूअर रेटिंग' को 'बीबीबी+' से बढ़ाकर 'ए- स्टेबल' कर दिया है। इसकी वजह अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बताया है। जेसीआर ने अपने नोट में कहा कि भारत की आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी हुई है और इसे निजी खपत और सरकारी निवेश का समर्थन मिल रहा है।

भारत सरकार की नीतियां भी लगातार आर्थिक वृद्धि में मदद कर रही हैं, इसमें डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू करना शामिल है। इससे देश का आर्थिक आधार पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। जेसीआर ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है और वित्त वर्ष 27 में इसके 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी से बढ़ने का अनुमान है। इसे इनकम टैक्स

■ अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को बताया मुख्य वजह

और जीएसटी में कटौती से सहारा मिल रहा है। हालांकि, मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण खाद्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस कारण से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यह अभी भी आरबीआई के लक्ष्य के अंदर बनी हुई है।

नोट में देश के बैंकिंग सेक्टर की सराहना करते हुए जेसीआर ने आगे कहा कि भारत का बैंकिंग सेक्टर मजबूत स्थिति में है और नॉन-परफॉरमिंग लोन रेश्यो 2 प्रतिशत की नीचे चला गया है।

चीनी नरम, चावल व खाद्य तेलों के दाम फिर बढ़े, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चीनी की कीमतों में लगातार छठे दिन गिरावट रही। वहीं, चावल और खाद्य तेलों के भाव एक बार फिर बढ़ गए। गेहूं में टिकाव देखा गया जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा।

मीठे के थोक बाजार में चीनी की औसत कीमत 41 रुपए घटकर 5,762 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। वहीं, गुड़ 23 रुपए महंगा हुआ और 5,999 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 39 पैसे घटकर 62.57 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत सात रुपए बढ़कर 4,147 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। गेहूं 2,846 रुपए प्रति क्विंटल के पिछले कारोबारी दिवस से स्तर पर स्थिर रहा। आटे का भाव भी कमोबेश अपरिवर्तित रहा। मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में नवंबर का पाम ऑयल वायदा 14 रिंगिट गिरकर 5,134 रिंगिट प्रति टन रह गया। दिसंबर का अमेरिकी सोया तेल वायदा भी 0.66 प्रतिशत फिसलकर 72.15 सेंट प्रति पौंड के भाव बोला गया।

स्थानीय बाजार में आज पाम ऑयल की औसत कीमत 71 रुपए और वनस्पति की 43 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गई। सूरजमुखी तेल 41 रुपए और सरसों तेल 28 रुपए महंगा हुआ। मूंगफली तेल 26 रुपए और सोया तेल 19 रुपए प्रति क्विंटल ऊपर रहा। सरकारी वेबसाइट पर जारी खाद्यान्नों के दिन के औसत थोक भाव इस प्रकार रहे : **दाल-दलहन :** दाल चना 7990.90 रुपए, मसूर काली 8235.65 रुपए, मूंग दाल 10201.04 रुपए, उड़द दाल 11348.28 रुपए, तुअर दाल 11438.14 रुपए प्रति क्विंटल रही।

आरबीआई की एफसीएनआर (बी) जमा स्कीम को निवेशकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, 2 सितम्बर (एजेंसियां)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से अमेरिकी डॉलर आकर्षित करने के लिए शुरू की गई विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) या (एफसीएनआर(बी)) जमा को निवेशकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 31 अगस्त, 2026 तक कुल 127 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है, जो कि अनुमान 100 अरब डॉलर से काफी ज्यादा है।

आरबीआई की ओर से जारी डेटा में कहा गया कि 31 अगस्त देश में एफसीएनआर (बी) जमा में 127.226 अरब डॉलर, बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) में 3.891 अरब डॉलर और विदेशों से विदेशी मुद्रा में उधार (ओएफसीबी) में 5.260 अरब डॉलर का इनफ्लो दर्ज किया गया है। आरबीआई ने रुपए की स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष अमेरिकी-डॉलर स्वैप सुविधा के तहत एफसीएनआर (बी), ईसीबी और ओएफसीबी स्कीम को 8 जून को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजनाओं

127 अरब डॉलर का इनफ्लो आया

को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। आरबीआई के मुताबिक, एफसीएनआर (बी) जमा 31 अगस्त तक ही निवेशकों के लिए खुली थी। वहीं, ईसीबी और ओएफसीबी योजनाओं में निवेशक 31 दिसंबर, 2026 तक निवेश कर सकते हैं। शुरुआत में आरबीआई ने एफसीएनआर (बी) जमा में निवेश की आखिरी तारीख 11 सितंबर, 2026 तय की थी, लेकिन निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए इसको संशोधित करके 31 अगस्त, 2026 कर दिया गया।

आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई की एफसीएनआर(बी) स्वैप सुविधा के तहत 17.88 अरब डॉलर जुटाए

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेष डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा के तहत विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर (बी) जमा के जरिए करीब 17.88 अरब डॉलर जुटाए हैं। बैंक ने बताया कि जुटाई गई राशि में से ऐसी जमाओं के बदले बैंक की अंतरराष्ट्रीय शाखाओं और सहायक कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण की राशि करीब 9 अरब डॉलर रही। वहीं, ऐसी जमाओं से समर्थित ऋण के बदले बैंक द्वारा अन्य ऋणदाताओं को जारी किए गए।

सार संक्षेप

अडाणी पोर्ट्स ने अगस्त में संभाला 5 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो

अहमदाबाद। एपीएसईजेड ने बुधवार को कहा कि अगस्त 2026 में कंपनी ने 5 करोड़ मीट्रिक टन कार्गो संभाला है। इसमें सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी ने कहा कि यह कंपनी द्वारा किसी एक महीने में संभाला गया, अब तक का सबसे अधिक कार्गो है, जो उसके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पोर्ट्स की क्षमता को दिखाता है। अगस्त में कार्गो ढुलाई में वृद्धि की वजह ड्राई कार्गो का सालाना आधार पर 25 प्रतिशत और कंटेनर वॉल्यूम का सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़ना था। एपीएसईजेड ने कहा कि यह प्रदर्शन उसकी अलग-अलग तरह से ग्रोथ करने की रणनीति की सफलता को दिखाती है, जिसमें विझिंजम और कोलंबो में ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशन्स की वजह से कंटेनर वॉल्यूम में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है।

सीसीपीए ने विस्फोटक पदार्थों को ऑनलाइन बेचने पर की कार्रवाई

मुंबई। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने बिना अनिवार्य सुरक्षा उपायों के विस्फोटक पदार्थों को ऑनलाइन बेचने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डायल4ट्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जानकारी उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्रवाई विनियमित खतरनाक और विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग और बिक्री के संदर्भ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की क्षेत्र-व्यापी जांच के बाद हुई है। इसमें लाइसेंस सत्यापन, खरीदार की पात्रता जांच और अनिवार्य सुरक्षा संबंधी जानकारी के बिना अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन लिस्टिंग की सुविधा देने के लिए डायल4ट्रेड दोषी पाया गया है।

उदय कोटक ने बढ़ती ग्लोबल बॉन्ड यील्ड को लेकर दी चेतावनी

नई दिल्ली। दिग्गज बैंकर उदय कोटक ने बुधवार को निवेशकों को बढ़ती ग्लोबल बॉन्ड यील्ड को लेकर चेतावनी देते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ता सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटे के चलते केंद्रीय बैंक को अपनी बैलेंट शीट को बढ़ना (अधिक मात्रा में नोट छपाना) पड़ सकता है। इससे महंगाई में इजाफा होगा और छोटी अवधि में अधिक ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब जापान के 10 साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड 3 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई है, जो कि 1996 के बाद अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। वहीं, अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.8 प्रतिशत के आसपास है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उदय कोटक ने लिखा कि सरकारी कर्ज और बढ़ते घाटे के कारण केंद्रीय बैंक के पास अपनी बैलेंसशीट को बढ़ाने यानी पैसा छापने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली देने का ऐलान

जिसके हाथ में हल, वही देश का असली बल : डॉ. यादव

ढाई वर्ष में सौ लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य

भोपाल/ग्वालियर, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिसके हाथ में हल है, वही देश का असली बल है। किसानों के परिश्रम को मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बीज से बाजार तक और खेत से निर्यात तक किसानों के साथ खड़ी है। अगले ढाई वर्ष में प्रदेश की सिंचित कृषि भूमि का रकबा 60 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री बुधवार को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव एवं सहकारी किसान समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने की बात कही।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना के सरलीकरण और कृषक कवच योजना का शुभारंभ किया। साथ ही 200 नई पैक्स संस्थाओं के कार्यालय तथा अपेक्स बैंक की ग्वालियर संभागीय शाखा का भी शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को वर्तमान वित्तीय स्थिति से उबारने के लिए आवश्यक सहायता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को खरीफ और रबी ऋण के लिए अलग-अलग छह माह में खाता पलटने की बाध्यता नहीं होगी और वे अपनी सुविधा से 12 माह में ऋण चुका सकेंगे। उन्होंने कृषि के साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, प्राकृतिक खेती और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि से एग्री-टेक और फूड प्रोसेसिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की समृद्धि का आधार है।

किसान विश्राम गृह के लिए 60 लाख रुपए मंजूर

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अब किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें रात में खेतों पर जाकर सिंचाई करने की मजबूरी से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को श्योपुर कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव एवं किसान मेले को ग्वालियर से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने श्योपुर के किसानों से संवाद करते हुए कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मंडी श्योपुर में किसानों के लिए नवीन विश्राम गृह निर्माण हेतु 60 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुआयामी योजनाओं पर काम हो रहा है। डॉ. यादव ने बताया कि किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। खरीफ और रबी फसलों के ऋण की वापसी अवधि में भी राहत देते हुए इसे अब ऋण लेने की तारीख से एक वर्ष तक कर दिया गया है।

पूर्व विधायक संजय शर्मा के कार्यालयों पर ईडी ने की सर्चिंग

नरसिंहपुर/भोपाल, देशबन्धु। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शर्मा के नरसिंहपुर और देवरी स्थित कार्यालयों सहित 14 स्थानों पर सर्चिंग की। यह कार्रवाई टोल वसूली से संबंधित बताई गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह ईडी की टीम नरसिंहपुर पहुंची। तेंदूखेड़ा व देवरी स्थित कार्यालयों में भी सर्चिंग की और दस्तावेज खंगाले। ईडी को नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टोल प्लाजा पर गड़बड़ी की जानकारी मिली है। इस मार्ग की टोल वसूली का काम संजय शर्मा की कंपनी के पास है। बताया जाता है कि टोल वसूली में अनधिकृत सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर फर्जी टोल रसीदें तैयार की जा रही थीं।

इस प्रक्रिया के जरिए टोल से वसूली गई रकम को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आधिकारिक अकाउंटिंग सिस्टम से बाहर डायवर्ट किया गया। फोरेंसिक परीक्षण और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रिकॉर्ड की जांच में ईडी ने अनधिकृत सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की पुष्टि की है। ईडी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता के कई स्थानों पर परिसरों भी तलाशी ली।

सरकार के इशारों पर काम कर रही ईडी : कांग्रेस

कांग्रेस के नरसिंहपुर शहर अध्यक्ष रोहित पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा- ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। सरकारी एजेंसियां संजय शर्मा की लोकप्रियता और आवाज को दबा नहीं सकतीं। वे और उनके साथ कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता जनता की आवाज उठाता रहेगा।

सार-समाचार

पटेल ने सुनी समस्याएं कहा- प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा समाधान

भोपाल, देशबन्धु। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना। इस दौरान पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक जनसमस्या का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। मंत्री पटेल ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जनसमस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। जिन प्रकरणों में विस्तृत प्रक्रिया अथवा संबंधित विभाग की कार्रवाई आवश्यक है, उन्हें शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित से जुड़े विषयों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

जीआईएस आधारित नवाचार के लिए मध्य प्रदेश को मिला अवार्ड

भोपाल, देशबन्धु। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त नेतृत्व और मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश नगरीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी तथा आधुनिक तकनीकों के समन्वय से प्रशासनिक दक्षता के नए मानदंड स्थापित कर रहा है। इसी श्रृंखला में राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विकसित एकीकृत जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म गरुड़ के उत्कृष्ट और नवोन्मेषी उपयोग के लिए मध्यप्रदेश को प्रतिष्ठित 'अचीवमेंट इन जीआईएस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में एसरी इंडिया निदेशक अजेन्द्र कुमार ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे को यह सम्मान प्रदान किया।

फर्जी शिक्षक नियुक्ति मामले में पांच के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

श्रीनगर, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक नियुक्ति आदेश के मामले में पांच लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आरोपपत्र बडगाम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।

राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम अब 19 सितंबर को

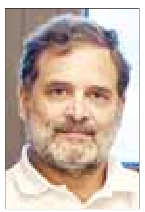

भोपाल, देशबन्धु। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का इंदौर में प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम अब 12 की जगह 19 सितंबर को होगा। कांग्रेस ने आयोजन के लिए नेहरू स्टेडियम में अनुमति चाही थी। लेकिन नगर निगम ने अदालत के आदेश का हवाला देते हुए स्टेडियम में आयोजन की अनुमति नहीं दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी इस आयोजन को राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहती। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए नया मैदान तैयार करना होगा और जो भी स्थान उपलब्ध कराएगा, कांग्रेस वहां आयोजन करेगी।

पटवारी ने कहा कि यह कोई सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छात्रों की शिक्षा, उनके भविष्य और रोजगार से जुड़े सवालों को उठाने का मंच है। राहुल गांधी ने देश के युवाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों की लड़ाई शुरू की है। उन्होंने दावा किया कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में 50 हजार से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है।

भाजपा लोकतंत्र की आवाज को दबाने का कर रही प्रयास : चौधरी

रोकने से सवाल खत्म नहीं होंगे : पटवारी

इंदौर, देशबन्धु। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार को छात्रों और युवाओं की आवाज से डरने के बजाय उसे सुनना चाहिए। 'छात्रों की गूंज' पूरी तरह युवाओं के सवालों और उनके भविष्य से जुड़ा कार्यक्रम है। लोकतंत्र में किसी भी विचार या संवाद से डरने के बजाय उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में देशभर में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 'छात्रों की गूंज' का उद्देश्य युवाओं के सपनों, उनकी समस्याओं और शिक्षा एवं रोजगार से जुड़े सवालों को सामने लाना है। पटवारी ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल के प्रचार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि देश के भविष्य, युवाओं के सपनों, शिक्षा के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था की सुरक्षा से जुड़ा सार्थक संवाद है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आयोजन के महत्व को समझते हुए नेहरू स्टेडियम उपलब्ध कराया जाए।

कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने की मैराथन बैठक

राहुल गांधी के 19 सितंबर को प्रस्तावित इंदौर दौरे और 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की मैराथन बैठक आयोजित की गई। राजनीतिक मामलों की समिति की इस बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ इंदौर एवं उज्जैन संभाग के कांग्रेस अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, मंडलम अध्यक्षों, मोर्चा एवं प्रकोष्ठ संगठनों के पदाधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि 19 सितंबर का आयोजन छात्रों और युवाओं की अधिकतम भागीदारी के साथ ऐसा मंच बने। बैठक में हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राहुल गांधी के सुरक्षा सलहाकर के.बी बैजू, मनोज त्यागी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, अजय सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, शोभा ओझा, सत्य नारायण पटेल, विजय लक्ष्मी साधो, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधायक, जिला अध्यक्ष एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

किसानों व शिक्षकों पर दर्ज आपराधिक मामले वापस लेगी तमिलनाडु सरकार

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु सरकार ने मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और अन्य वैध मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों को वापस लेने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इस निर्णय की घोषणा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकार तथा आम नागरिकों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास बताया। यह आदेश तिरुवनमलाई जिले में प्रस्तावित तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम के औद्योगिक एस्टेट का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ दायर मामलों को कवर करेगा। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि कांचीपुरम जिले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामले भी वापस ले लिए जाएंगे। परंदूर और आसपास के गांवों के निवासियों ने हवाई अड्डे की परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे, उनका तर्क था कि इससे उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण होगा, जल निकायों को नुकसान होगा और आय के पारंपरिक स्रोत नष्ट हो जाएंगे।

घर-घर गोकुल, घर-घर गोपाल' से गूंजेगा प्रदेश, कृष्णमय होगा माहौल

भोपाल, देशबन्धु। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश इस बार व्यापक सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनेगा। संस्कृति विभाग के श्रीकृष्ण पाथेय न्यास द्वारा 4 सितंबर को 'श्रीकृष्ण पर्व' का राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। 'घर-घर गोकुल, घर-घर गोपाल' की संकल्पना के साथ प्रदेश के सभी 55 जिलों में 111 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

- जन्माष्टमी पर 55 जिलों के 111 स्थलों पर सांस्कृतिक आयोजन
- 75 सौ से अधिक मंदिरों की होगी विशेष साज-सज्जा

प्रदेश के 7500 से अधिक श्रीकृष्ण मंदिरों में विशेष साज-सज्जा की जाएगी, जबकि 1500 से अधिक स्थानीय कलाकार श्रीकृष्ण की लीलाओं, भक्ति, मित्रता और सांस्कृतिक परंपराओं पर केंद्रित प्रस्तुतियां देंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में 101 से अधिक बच्चे राधा-कृष्ण की वेशभूषा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बच्चों को माखन-मिश्री, लड्डू गोपाल की प्रतिमा और श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित पुस्तकें भेंट करेंगे।

राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि श्रीकृष्ण पर्व का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों और गौरवशाली विरासत से जोड़ना है। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम और नारायणा धाम, धार के अमझेरा, महू के जानापाव, रायसेन के जामगढ़ सहित अनेक ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। जानापाव में मुख्यमंत्री डॉ. यादव परशुराम-श्रीकृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। वहीं नारायण धाम में पांच दिवसीय सांस्कृतिक श्रृंखला में कृष्ण-सुदामा मित्रता, गुरु-शिष्य परंपरा, माखन चोरी, बाल लीला और गीता उपदेश जैसे प्रसंग मंचित किए जाएंगे। प्रदेशभर में रासलीला, नृत्य-नाटिका, भजन और लोकगायन के माध्यम से श्रीकृष्ण के जीवन-दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी है। इस अवसर पर कृष्ण पाथेय न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीराम तिवारी भी मौजूद थे।

फर्जी वकालतनामे संबंधी मामले में कोर्ट सख्त

शिक्षक को वकील बताने का आरोप, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

जबलपुर, देशबन्धु। हाईकोर्ट ने फर्जी वकालतनामे और शपथपत्र में कथित रूप से गलत जानकारी देने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने पाया कि जिस नीरज कुमार साकेत को अधिवक्ता बताया गया था, वह वास्तव में रीवा जिले के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी के गेस्ट लेक्चरर, ग्रेड टू के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के शपथपत्र में नीरज साकेत को अधिवक्ता बताए जाने को प्रथमदृष्टया गलत जानकारी माना। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग, रीवा सेंट्रल जेल प्रशासन व एमपी स्टेट बार काउंसिल को अलग-अलग जांच कर 30 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई में यह भी सामने आया कि नीरज साकेत ने राम प्रकाश यादव के लिए 30 वकालतनामे प्राप्त किए थे। कोर्ट ने कहा कि यदि उनका किसी आरोपित से पारिवारिक संबंध भी हो, तो अन्य आरोपितों के वकालतनामे प्राप्त करने का अधिकार नहीं बनता। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार रीवा सेंट्रल जेल से अधिवक्ता राम प्रकाश यादव के लिए 300 से अधिक वकालतनामे प्राप्त किए गए। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए। रीवा जेल के तत्कालीन अधीक्षक की भूमिका की भी जांच होगी, जबकि स्टेट बार काउंसिल अधिवक्ता के खिलाफ गलत शपथपत्र के मामले में कार्रवाई करेगी।

> शिक्षा विभाग, जेल प्रशासन और स्टेट बार काउंसिल से 30 दिन में रिपोर्ट तलब

विवि से राजीव गांधी का नाम हटाए जाने पर कांग्रेस नेताओं ने जताया कड़ा एतराज

इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही सरकार : पटवारी

भोपाल, देशबन्धु। कांग्रेस ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) को 3 हिस्सों में बांटने और राजीव गांधी का नाम हटाने पर कड़ा एतराज जताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रही है या इतिहास मिटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का नाम हटाया जा सकता है, लेकिन देश के लिए उनका योगदान नहीं मिटाया जा सकता। कांग्रेस नेता ने इसे भाजपा सरकार की संकीर्ण मानसिकता बताते हुए चेतावनी दी कि सरकार आज जैसा करेगी, भविष्य में वैसा ही परिणाम भुगतेगी।

सरकार की ओछी मानसिकता : कमलनाथ

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे भाजपा सरकार की ओछी मानसिकता बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश में सूचना क्रांति और कंप्यूटर के युग का सूत्रपात राजीव गांधी ने किया था। भाजपा खुद तो कोई नया काम कर नहीं पाती, बस नाम और नाम पट्टिकाएं बदलने में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि याद रहे कल के बाद परसों भी आता है। हर अच्छे-बुरे काम का हिसाब होता है। आप नाम बदलकर इतिहास नहीं बदल सकते।

नाम हटाना राजनीति से प्रेरित : अजय

पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य की भाजपा सरकार द्वारा राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को तीन हिस्सों में बांटने और उससे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने के फैसले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रेरित कदम बताते हुए कहा कि नाम बदल देने से इतिहास के पन्नों और जनता के दिलों से राजीव गांधी के योगदान को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक सुनियोजित साजिश के तहत इस प्रतिष्ठित संस्थान को विलोपित किया जा रहा है।

दिलों से नहीं हटाया जा सकता राजीव का नाम : सिंघार

विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम किया। इस वजह से आज विश्व में हमारा नाम है। सिंघार ने कहा कि राजीव गांधी का नाम किसी संस्था से हटाया जा सकता है, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि विश्वविद्यालय का नाम बदलने से छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को क्या फायदा होगा?

राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की तैनाती का कोई मतलब नहीं : प्रसाद

लखनऊ, एजेंसी। अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने महाराष्ट्र एसआईआर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की तैनाती और नेपाल बाढ़ पर प्रतिक्रियाएं दी। श्रीराम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा सीईओ की तैनाती किए जाने पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि सीईओ की तैनाती का कोई मतलब नहीं है। इस पद पर चाहे आईएएस हो या आईपीएस, उसे सरकार के दबाव में काम करना पड़ेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चंदा चोरी का खुलासा किया था। इस खुलासे को 2 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन कारगर और सार्थक काम नहीं हुआ है। हालांकि, बड़ी मछलियों को बचाने का काम किया गया है। यह चोरी और डकैती प्रभु श्रीराम दरबार की है। सरकार भले ही आरोपियों को बचा ले, लेकिन वे बचेंगे नहीं। जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब किसी शक्ति का उदय होता है। महाशक्ति ही पापियों का नाश करती है। यहां तो प्रभु श्रीराम स्वयं विद्यमान हैं, इनका नाश होना है।

चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों के बीच लगातार राहत पहुंचा रही राज्यसभा सांसद तन्खा की टीम

चित्रकूट, देशबन्धु। चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के मार्गदर्शन में राहत अभियान लगातार जारी है।

उनकी टीम द्वारा प्रभावित गांवों एवं आदिवासी बस्तियों में घर-घर पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री,कपड़े सहित आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज देवलहा कोलान एवं मिचकुरिन आदिवासी बस्ती में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को साड़ियां और राशन सामग्री वितरित की गई। कांग्रेस नेता एवं किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आशुतोष द्विवेदी ने स्वयं प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। राहत अभियान के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक लगातार आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा और सहयोग का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत सामग्री मिलने पर राज्यसभा सांसद तन्खा और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता एवं सहयोगी भी उपस्थित रहे।

निर्माण, परीक्षण और नवाचार का प्रस्तुत किया रोडमैप

प्रदेश को बनाया जाएगा ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र

ड्रोन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ किया मंथन

भोपाल, देशबन्धु। मध्य प्रदेश को ड्रोन निर्माण, परीक्षण, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईआईएसईआर भोपाल एवं ड्रोन क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ उच्चस्तरीय इंडस्ट्री राउंडटेबल आयोजित किया गया। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन ने चर्चा में सहभागिता करते हुए ड्रोन क्षेत्र के विकास, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की प्राथमिकताओं को साझा किया।

राउंडटेबल में ड्रोन क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और इकोसिस्टम से जुड़े प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इनमें गरुड़, डीएफआई, आइडियाफोर्ज, एनएफएसयू, प्रखर और आईजेडआई सहित अनेक कंपनियों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिभागियों ने प्रदेश में ड्रोन निर्माण, परीक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बैठक में ड्रोन क्षेत्र के लिए आवश्यक अधोसंरचना, परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं, कौशल विकास, अनुसंधान सहयोग और ग्वालियर में प्रस्तावित ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग क्लस्टर के विकास पर विस्तार से चर्चा हुई।

राउंडटेबल में आईआईएसईआर भोपाल में ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के राज्य शासन के निर्णय को सराहा गया। इसका उद्देश्य उन्नत अनुसंधान, उत्पाद विकास, स्टार्टअप इनक्यूबेशन, प्रौद्योगिकी सत्यापन और नई पीढ़ी के ड्रोन अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। जुलाई 2026 में मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने लगभग 85.51 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को स्वीकृति दी है। ग्वालियर में प्रस्तावित ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग क्लस्टर में ड्रोन निर्माण, प्रोटोटाइपिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, प्रमाणन और फ्लाइट टेस्टिंग के लिए एकीकृत अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इंडस्ट्री राउंडटेबल से प्राप्त सुझावों को प्रदेश के ड्रोन इकोसिस्टम के विकास के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप में शामिल किया जाएगा। ये सुझाव ग्वालियर क्लस्टर, आईआईएसईआर भोपाल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर सृजित करने की आगामी पहलों के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेंगे। बैठक में मध्यप्रदेश ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी-2025 के महत्व को भी रेखांकित किया गया। नीति का उद्देश्य निवेश, नवाचार, कौशल विकास, प्रमाणन सहयोग तथा कृषि, लॉजिस्टिक्स, अधोसंरचना, सुशासन, आपदा प्रबंधन और औद्योगिक अनुप्रयोगों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना है।

पत्रकार प्रकाशन प्रा.लि. के लिए गिरिराज चाचा द्वारा श्री सिद्धि विनायक प्रिंटर्स, प्लाट नं. 26 बी देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. 462011 से मुद्रित एवं प्रकाशित, संपादक: **पलाश सुरजन,** कार्यकारी संपादक: **ज़ाकिर अली*** फोन 0755-4222971, ई-मेल deshbandhubpl1@yahoo.co.in प्रेस पंजीयन-प.स. 45096/85 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार।